सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 278, नई दिल्ली । मंगलवार, 17 दिसम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा।

03 दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

06 जलवायु पर बढ़ते संकट के जिम्मेदार

08 न्यायालय ने दोनों पक्षो को सुनने के उपरांत मुलज़ीमानों को किया दोषमुक्त

परिवहन आयुक्त द्वारा जारी आदेश से उत्पन्न व्यवसायिक वाहन मालिकों को वाहन जांच परेशानियों से अभी तक नहीं मिली निजात

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली में व्यवसायिक गतिविधि में शामिल वाहनों को वाहन जांच प्रमाण पत्र लेने में आ रही परेशानी के हल के लिए दिल्ली के सभी वाहन मालिक, चालक और व्यवसाई लगातार गुहार लगा रहे हैं पर उसके बाद भी अभी तक कोई हल निकल कर सामने नहीं आया।

भारत देश के परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, भाजपा अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश सचदेवा और नर्व नियुक्त मंत्री राघवेंद्र शौकीन तक द्वारा दिए आश्वाशन भी अभी तक हवा में नजर आ रहे हैं।

आखिर परिवहन आयुक्त द्वारा बिना सोचे समझे बिना जांच पड़ताल किए ऐसे फरमान जो 2018 में स्वयं उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर आसीन अरविंद केजरीवाल द्वारा करने के बाद वाहन मालिकों और जनता की परेशानियों को देखते हुए तत्काल वापिस लेना पड़ा था उस पर कोई कार्य किए बिना जारी करना और उसके बाद आदेश के बाद सभी विभागीय कमियों के कारण हो रही वाहन मालिकों और जनता की परेशानियों को देखते हुए भी वापिस नहीं लेना का अर्थ क्या समझे।

क्या परिवहन आयुक्त दिल्ली उपराज्यपाल से भी ज्यादा शक्ति के धारक हैं या उनको उपराज्यपाल की ही शय प्राप्त है?

यह प्रश्न इस लिए भी मुख्य है क्योंकि

1. परिवहन राज्य मंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार तक इस बात को मानते हैं की यह आदेश गलत है फिर भी वापिस नहीं किया गया आज तक,

2. तकनीकी पदों पर गैर तकनीकी अधिकारी को नियुक्त करना वह भी माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दिल्ली, कैट, सर्विस रुल और सचिव न्याय विभाग दिल्ली के दिशा निर्देशों के विरुद्ध जाकर,

3. जनता के घरों में खड़े वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर उठवाकर उन बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलरो जो सड़क परिवहन एवम्-राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ब्लैक लिस्टेड है के साथ दिल्लीवासियों के पहले से प्राप्त वाहनों की पेमेंट नहीं देने वालो को सुपुर्द करवाने के आदेश जारी करने,

4. दिल्ली में राजपत्र अधिसूचना द्वारा जनहित में चालित क्षेत्रीय शाखाओं को विलय करने,

इत्यादि अनेक जनता को परेशान करने और अहित करने के आदेश जारी करते आ रहे है पर उसकी पूर्ण जानकारी होते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्य सचिव दिल्ली या मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार द्वारा भी कोई सवाल जवाब तक नहीं किया गया और ना ही जनता के अहित और कानून के विरुद्ध जारी परिवहन आयुक्त के आदेशों को वापिस करवाया, आखिर क्यों?

क्या दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों पर इस तरह के आदेश परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किए जा रहे हैं जो राजस्व में इजाफा और बड़े व्यवसायिक कंपनियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से परिपूर्ण है, सवाल तो उठता ही है?

दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 फिर से लागू इन पाबंदियों का करना होगा पालन

इस चरण के तहत निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कार्यों पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इसके अलावा निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। एनसीआर राज्यों से अंतर-राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों को राहत दी गई है।

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रैप-3 के प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए गए हैं। सीएक्यूएम की उप-समिति ने सोमवार को यह फैसला लिया। निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध अंतर-राज्यीय बसों के प्रवेश पर रोक जैसे उपाय किए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों सीएनजी वाहनों को छूट दी गई है।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस कारण दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 के प्रतिबंध लागू करने का फैसला लिया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की उप-समिति ने यह फैसला लिया। बता दें, 13 दिसंबर को जारी संशोधित ग्रैप-3 के नियम लागू होंगे। इसे पूरे दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

इस चरण के तहत निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कार्यों पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इसके अलावा निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। एनसीआर राज्यों से अंतर-राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों को राहत दी गई है।

सोमवार को एक्यूआई 351 किया गया रिकॉर्ड

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार सोमवार सुबह दिल्ली का एयर इंडेक्स 351 रहा जो बेहद खराब श्रेणी में है। कई इलाकों का एक्यूआई 400 के आसपास रहा। आइक्यूएयर ने सुबह में दिल्ली का एयर इंडेक्स 348 बताया। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में अभी दो दिन हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में ही रह सकती है।

ग्रैप तीन में ये प्रतिबंध होंगे लागू

ग्रैप तीन में दिव्यांग लोगों को दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले में व्यक्तिगत जरूरत के लिए बीएस तीन पेट्रोल इंजन और बीएस चार डीजल इंजन के हल्के वाहन (कार) का इस्तेमाल की छूट रहेगी।

दिल्ली में माल ढुलाई के लिए बीएस चार के डीजल इंजन वाले एमजीवी (मीडियम गूड्स व्हीकल) पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रतिबंध से सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट रहेगी।

दिल्ली से बाहर पंजीकृत बीएस चार और उससे कम मानक के डीजल इंजन वाहनों को ग्रैप तीन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश वर्जित रहेगा। पहले ये प्रावधान चौथे चरण में शामिल थे।

ग्रैप तीन में दिल्ली एनसीआर के स्कूल पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में करा सकते हैं। अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास का विकल्प चयन कर सकते हैं।

ग्रैप तीन में दिल्ली सरकार और एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारें सरकारी विभागों और सिविक एजेंसियों के कार्यालय के समय में बदलाव कर सकती हैं।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

दिल्ली एयरपोर्ट ने बनाया नया रिकॉर्ड, बन गया देश का ऐसा पहला एयरपोर्ट जो...

दिल्ली एयरपोर्ट ने एक और उपलब्धि हासिल की है। यह देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जो 150 गंतव्यों से जुड़ता है। रविवार को थाई एयरएशिया एक्स ने दिल्ली और बैंकॉक-डॉन मुआंग (डीएमके) के बीच सीधी उड़ानें शुरू कीं जो दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ने वाला 150वां गंतव्य है। आगे विस्तार से पढ़िए इस रिपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर और क्या-क्या अपडेट है।

नई दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है, जो 150 गंतव्यों से जुड़ता है। रविवार को थाई एयरएशिया एक्स ने दिल्ली और बैंकॉक-डॉन मुआंग (डीएमके) के बीच सीधी उड़ानें शुरू कीं, जो दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ने वाला 150वां गंतव्य है।

20 से ज्यादा विशेष अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ा

यह नया रूट एयरबस ए330 विमानों के साथ सप्ताह में दो बार संचालित होगा, जनवरी 2025 के मध्य तक इसे बढ़ाकर सप्ताह में चार बार करने की योजना है। एक बयान में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली एयरपोर्ट ने 20 से ज्यादा विशेष अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ा है, जिनमें नोम पेन्ह, बाली डेनपसार, कैलगरी, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, वाशिंगटन डलेस, शिकागो ओ'हारे और टोक्यो हनेडा शामिल हैं।

पिछले एक दशक में एयरपोर्ट ने ट्रांसफर यात्रियों में 100 प्रतिशत की वृद्धि का अनुभव किया है, जिसने दक्षिण एशिया में एक अग्रणी ट्रांजिट हब के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत किया है।

दिल्ली से जुड़ी हुई हैं 88 प्रतिशत जगहें

भारत से लंबी दूरी की सभी जगहों में से 88 प्रतिशत जगहें दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और भारत से रवाना होने वाली सभी लंबी दूरी की साप्ताहिक उड़ानों में से 56 प्रतिशत दिल्ली हवाई अड्डे से संचालित होती हैं। भारत से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लगभग 50 प्रतिशत (सटीक रूप से 42 प्रतिशत) यात्री दिल्ली को अपना प्रवेश द्वार चुनते हैं।

दिल्ली हवाई अड्डा सालाना चार मिलियन घरेलू यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए निर्बाध कनेक्शन प्रदान करता है। भारतीय वाहकों द्वारा वाइड-बॉडी विमानों की निरंतर शुरूआत दिल्ली हवाई अड्डे को एक सुपर-कनेक्टर हब में बदलने के लिए तैयार है, जो अंतर्राष्ट्रीय और लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक अग्रणी विकल्प के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करेगा।

विमानन के एक नए युग में ले जाने पर गर्व

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ विदेह कुमार जयपुरियार ने कहा, ₹150 गंतव्यों को जोड़ने का यह मील का पत्थर वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ाने और विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमें भारत को विमानन के एक नए युग में ले जाने पर गर्व है और हम दुनिया भर के यात्रियों के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए समर्पित हैं।"

दिल्ली हवाई अड्डे की अत्याधुनिक अवसंरचना, यात्री-केंद्रित सुविधाएं और कुशल स्थानांतरण प्रक्रियाओं ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे यह विमानन उद्योग में उत्कृष्टता का एक मानक बन गया है।

काली, पीली, हरी या लाल? कौन-सी किशमिश है सेहत के लिए ज्यादा बेहतर, एक क्लिक में दूर करें कन्फ्यूजन

आपने कभी गौर किया है कि किशमिश कई रंगों की होती हैं- काली पीली हरी और लाल लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी रंगों की किशमिश में से सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन-सी होती हैं? अगर नहीं तो यह आर्टिकल आप ही के लिए है। यहां हम आपको आसान शब्दों में चारों किशमिश का फर्क समझाने जा रहे हैं।

नई दिल्ली। सेहतमंद रहने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छे खानपान की जरूरत होती है। बीमारियों से बचने के लिए खाने में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जैसे पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स को डाइट में शामिल करना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स खाने के साथ-साथ रोजाना एक मुट्ठी ड्रायफ्रूट्स खाने की भी सलाह देते हैं। ड्रायफ्रूट्स में किशमिश का सेवन करना भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। किशमिश में आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं। ऐसे में, आइए इस आर्टिकल में आपको काली, पीली, हरी और लाल किशमिश के पोषक तत्वों की जानकारी देते हैं और बताते हैं कि तीनों में सबसे ज्यादा फायदेमंद (Raisins Benefits) कौन-सी किस्म है।

काली किशमिश

काली किशमिश, अपनी खास बनावट और स्वाद के लिए जानी जाती है। यह आयरन और अन्य न्यूट्रिएंट्स का एक शानदार सोर्स है, जो शरीर को एनर्जी देते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार होते हैं। काली किशमिश में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, शरीर की इम्युनिटी पावर को बढ़ाते हैं। दुनिया भर में, काली किशमिश सबसे ज्यादा लोकप्रिय किशमिश की किस्मों में से एक है।

पीली किशमिश

पीली किशमिश या सुनहरी किशमिश, अपनी मीठी और स्वादिष्ट पहचान के कारण फूड आइटम्स में बड़े तौर पर यूज की जाती है। इसे विभिन्न प्रकार के अंगूरों से तैयार किया जाता है। पीली किशमिश न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत को भी कई फायदे देती है। इसमें मौजूद नेचुरल शुगर, ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखने में मदद करती है। इसके अलावा, यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में भी मददगार होती है।

हरी किशमिश

हरी किशमिश अपनी छोटी और लंबी बनावट के कारण आसानी से पहचानी जा सकती है। इसे हरे अंगूरों से तैयार किया जाता है। इतना ही नहीं, हरी किशमिश आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन-सी से भरपूर होती है। ये पोषक तत्व शरीर को एनर्जी देते हैं और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में मददगार होते हैं।

लाल किशमिश

लाल किशमिश, लाल अंगूरों से बनाई जाती है और अपने मीठे और खट्टे स्वाद के लिए जानी जाती है। इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फाइबर और अन्य जरूरी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने, हड्डियों को मजबूत बनाने, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने और इम्युनिटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, लाल किशमिश हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है।

कौन-सी किशमिश है सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद?

असल में, इनमें से कोई भी किशमिश सेहत के लिए बुरी नहीं है। हर रंग की किशमिश में अलग-अलग पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को अलग-अलग तरीके से फायदा पहुंचाते हैं। जैसे, काली किशमिश में आयरन भरपूर होता है जो खून की कमी दूर करने में मदद करता है। वहीं, पीली किशमिश में फाइबर होता है जो पाचन को बेहतर बनाता है। तो ऐसे में, आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी किशमिश खा सकते हैं।

सर्दियों में इस रेसिपी से बनाएं 'हरा भरा कबाब', नहीं महसूस होगी रेस्टोरेंट की कमी

सर्दियों के मौसम में रजाई में दुबके-दुबके क्या खाएं यह सवाल हर किसी के मन में आता है। इस मौसम में अगर आप भी कुछ नया और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो हरा भरा कबाब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। स्वादिष्ट होने के साथ-साथ यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। आइए जानें इसे बनाने की आसान रेसिपी।

नई दिल्ली। सर्दियों में रजाई के अंदर गरमागरम स्नैक्स का मजा लेने से बड़ा आनंद कुछ नहीं होता। ऐसे में, अगर आप भी कुछ हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स ढूंढ रहे हैं तो हरा भरा कबाब (Hara Bhara Kebab) आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। हरी सब्जियों से भरपूर ये कबाब न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। आज हम आपको बताएंगे कि आप घर पर ही आसानी से हरा भरा कबाब कैसे बना सकते हैं। खास बात है कि इस रेसिपी (How To Make Hara Bhara Kebab) के साथ हरी चटनी सर्व करके आप सर्दियों के मौसम का पूरा मजा ले सकते हैं। आइए जानें।

हरा भरा कबाब बनाने के लिए सामग्री

पालक - 250 ग्राम
मटर - 100 ग्राम
पनीर - 100 ग्राम
आलू - 2 मीडियम शेप के
प्याज - 1 मीडियम शेप का
लहसुन - 3-4 कली
अदरक - 1 इंच का टुकड़ा
हरी मिर्च - 2
धनिया पत्ती - 1/2 कप
कसूरी मेथी - 1 चम्मच
गरम मसाला - 1/2 चम्मच
धनिया पाउडर - 1 चम्मच
जीरा पाउडर - 1/2 चम्मच
लाल मिर्च पाउडर - 1/4 चम्मच
अमचूर पाउडर - 1/4 चम्मच
नमक - स्वादानुसार
तेल - तलने के लिए
ब्रेड क्रम्ब्स - 1/2 कप
दही - 1/2 कप
पुदीना पत्ती - 1/4 कप

हरा भरा कबाब बनाने की विधि

सबसे पहले पालक, मटर और आलू को अच्छी तरह से धोकर कुकर में डालें। थोड़ा सा नमक और पानी डालकर कुकर की 2-3 सीटी लगा दें। सब्जियां पूरी तरह से गल जाने के बाद उन्हें ठंडा करके मिक्सर में पीस लें।

अब प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को पीसकर पेस्ट बना लें। एक पैन में तेल गरम करें और इस पेस्ट को भून लें। इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

इसके बाद पिसी हुई सब्जियों के मिश्रण में पनीर, कसूरी मेथी, धनिया पत्ती और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। फिर इसमें भूना हुआ मसाला डालकर मिलाएं।

फिर इस मिश्रण से छोटे-छोटे कबाब बना लें। प्रत्येक कबाब को ब्रेड क्रम्ब्स में लपेट लें।

अब एक कड़ाही में तेल गरम करें और कबाब को सुनहरा होने तक तल लें।

फिर दही, पुदीना पत्ती, नमक और थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सर में पीस लें।

अब तले हुए कबाब को दही की चटनी के साथ सर्व करें।

स्पेशल टिप्स

आप कबाब को तलने की बजाय ओवन में भी बेक कर सकते हैं।

कबाबों में अपनी पसंद के मुताबिक और भी सब्जियां जैसे गाजर, बीन्स आदि डाल सकते हैं।

आप कबाबों को फ्रिज में रखकर बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

एक महीने तक रोजाना भुने हुए बादाम खाएंगे आप, तो सेहत में नजर आएंगे कई जबरदस्त सुधार

सर्दियों में बादाम शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस मौसम में बादाम को भूनकर खाने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं? अगर नहीं तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। यहां हम आपको बताएंगे कि रोजाना एक महीने तक भुने हुए बादाम खाने से सेहत में क्या-कुछ सुधार हो सकते हैं।

बादाम तो आप खाते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भुने हुए बादाम भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं? जी हां, दिमाग को तेज करने से लेकर हड्डियों को मजबूत बनाने तक, भुने हुए बादाम कई तरह से फायदेमंद हैं। आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि किन लोगों को इन्हें खाने से ज्यादा फायदा मिलता है और रोजाना एक महीने तक डाइट में भुने हुए बादाम (Roasted Almonds For One Month) शामिल करने से हेल्थ में क्या-कुछ सुधार हो सकते हैं।

बैड कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा

बादाम को भूनकर खाने से हमारे शरीर में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन (HDL) यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बादाम में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड न केवल हार्ट हेल्थ के लिए बल्कि सेहत से जुड़े कई अन्य फायदों के लिए भी जाना जाता है। यह लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन (LDL) यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है और साथ ही HDL को बढ़ावा देता है।

मजबूत हड्डियां

हड्डियों की मजबूती के लिए भुने हुए बादाम एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये न सिर्फ हड्डियों को हेल्दी रखते हैं बल्कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से भी बचाते हैं। बादाम में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य आवश्यक पोषक तत्व बोन डेंसिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे हड्डियां मजबूत और लचीली बनती हैं।

बीपी करे कंट्रोल

बीपी के मरीजों के लिए भूने हुए बादाम एक बेहतरीन स्नैक ऑप्शन हैं। इनमें मौजूद मैग्नीशियम ब्लड वेसल्स को आराम पहुंचाता है और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक नियमित रूप से बादाम का सेवन करने से हार्ट हेल्थ बेहतर होता है और सेहत से जुड़े कई अन्य फायदे भी मिल सकते हैं।

हेल्दी स्किन

बादाम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और गुड फैट त्वचा में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिससे झुर्रियां कम होती हैं और त्वचा जवां दिखती है। इसके अलावा, ये त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं और उसे हेल्दी रखते हैं, जिससे आपकी त्वचा नेचुरली ग्लोइंग हो जाती है।

घरेलू विवाद से दहेज़ के झूठे मामलों में उलझते पुरुष

जब वैवाहिक कलह के कारण घरेलू विवाद उत्पन्न होते हैं, तो अक्सर पति के परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने की कोशिश की जाती है। ऐसे में अदालतों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि किसी कानून का दुरुपयोग कर किसी निर्दोष को न फंसाया जा सके। अदालतों को दहेज उत्पीड़न के मामलों में कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें सतर्क रहना होगा कि कहीं कानून का दुरुपयोग कर पति के रिश्तेदारों को फंसया तो नहीं जा रहा। अदालतों को निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाना चाहिए।

-प्रियंका सौरभ

पुरुषों के अधिकारों से तात्पर्य कानूनी और सामाजिक अधिकारों से है, जो ख़ास तौर पर पुरुषों के सामने आने वाली समस्याओं को सम्बोधित करते हैं। भारत में, जबकि महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना ज़रूरी है, पुरुषों की चुनौतियों पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है, जैसे कि धारा 498ए आईपीसी के तहत घरेलू हिंसा के मामलों में झूठे आरोप, मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी और सीमित पैतृक अधिकार। साझा पालन-पोषण कानूनों के इर्द-गिर्द हाल की बहसें लैंगिक न्याय के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करती हैं। भारत में पुरुषों के अधिकारों को अक्सर लैंगिक समानता पर व्यापक चर्चा में कम ध्यान दिया जाता है। घरेलू दुर्व्यवहार के शिकार के रूप में पुरुषों को कानूनी मान्यता नहीं मिलती है, जिससे सुरक्षा की मांग करना या दुर्व्यवहार के मामलों की रिपोर्ट करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जीवनसाथी द्वारा भावनात्मक, वित्तीय या शारीरिक शोषण के शिकार पुरुषों को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 जैसे मौजूदा ढाँचों के तहत कानूनी सहारा नहीं मिलता है।

पुरुषों से भावनाओं को दबाने की सामाजिक अपेक्षाएँ उनके मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करती हैं, जिससे आत्महत्या की दर और अनुपचारित मनोवैज्ञानिक समस्याएँ बढ़ती हैं। 2022 के एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि आत्महत्या के 72.5% मामले पुरुषों के हैं, जो लिंग-संवेदनशील मानसिक स्वास्थ्य नीतियों की आवश्यकता पर बल देता है। तलाक या अलगाव कानून मातृ हिरासत का पक्ष लेते हैं, पिता की भूमिका को हाशिए पर डालते हैं और बच्चे के पालन-पोषण में उन्हें समान अधिकारों से वंचित करते हैं। अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890, मातृ हिरासत को प्राथमिकता देता है जब तक कि माँ को अयोग्य नहीं माना जाता है, जिससे माता-पिता की भागीदारी के लिए पिता के अवसर सीमित हो जाते हैं। धारा 498ए (दहेज उत्पीड़न) जैसे लिंग-विशिष्ट कानूनों का कभी-कभी दुरुपयोग किया जाता है, जिससे निर्दोष पुरुषों को प्रतिष्ठा, वित्तीय और भावनात्मक नुक़सान होता है। राजेश शर्मा बनाम यूपी राज्य (2017) में, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498ए के दुरुपयोग को नोट किया और झूठे आरोपों के खिलाफ सुरक्षा उपाय पेश किए।

पुरुषों के पास शिकायतों को दूर करने के लिए समर्पित संस्थान या हेल्पलाइन का अभाव है सामाजिक रूढ़िवादिता पुरुषों को अपराधी के रूप में चित्रित करती है, संस्थागत दृष्टिकोण को प्रभावित करती है और कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार या यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में उचित उपचार को सीमित करती है। विशाखा दिशा-निर्देश केवल महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर उत्पीड़न को कवर करते हैं, जिससे पुरुष पीड़ितों को भारतीय कानून के तहत समान सुरक्षा नहीं मिलती है। यौन शोषण के वयस्क पुरुष उत्तरजीवी कानूनी ढांचे में अपरिचित रहते हैं, जिससे उन्हें वैधानिक उपचार या संस्थागत सहायता से वंचित रखा जाता है। उदाहरण के लिए, आईपीसी की धारा 375 बलात्कार को केवल एक महिला के दृष्टिकोण से परिभाषित करती है, जिससे यौन उत्पीड़न के पुरुष उत्तरजीवी बिना किसी सहारे के रह जाते हैं। लिंग-तटस्थ कानूनों के लिए लिंग न्याय के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए नीति सुधार।

घरेलू हिंसा अधिनियम और आईपीसी की धारा 498ए जैसे मौजूदा कानूनों को संशोधित करके उन्हें लिंग-तटस्थ बनाया जाए, जिससे घरेलू हिंसा और झूठे आरोपों के खिलाफ पुरुषों के लिए समान सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कनाडा और यूके जैसे देशों में, घरेलू हिंसा कानून लिंग-तटस्थ हैं यह पैतृक शिकायतों को सम्बोधित करते हुए बच्चे के सर्वोत्तम हितों को बढ़ावा देता है। साझा पालन-पोषण की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया में अच्छी तरह से स्थापित है, जो हिरासत के निर्णयों में दोनों माता-पिता के लिए समान विचार को अनिवार्य बनाती है। कार्यस्थल कल्याण कार्यक्रमों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करके और जागरूकता अभियान बनाकर पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने वाली समर्पित नीतियाँ स्थापित करें। जापान ने तनाव कम करने को लक्षित करते हुए कार्यस्थल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिन्हें लिंग-विशिष्ट चिंताओं को शामिल करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

झूठे आरोपों को सम्बोधित करना: कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के मामलों में झूठे आरोपों को रोकने और दंडित करने के लिए कड़े तंत्र लागू करें। लैंगिक न्याय के प्रति संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत उपाय पुरुष कल्याण आयोगों की स्थापना है। कानूनी सहायता और परामर्श सहित पुरुषों से जुड़े विशिष्ट मुद्दों को सम्बोधित करने के लिए महिला आयोगों के समान राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर वैधानिक निकाय बनाएँ। यूनाइटेड किंगडम में एक ₹पुरुष और लड़के गठबंधन₹ है जो मानसिक स्वास्थ्य और पैतृक अधिकारों जैसे मुद्दों की वकालत करता है। घरेलू हिंसा या दुर्व्यवहार के पुरुष पीड़ितों के लिए तत्काल सहायता और सहायता तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए लिंग-तटस्थ हेल्पलाइन और आश्रय स्थापित करें। भारत में (हिंसा और दुर्व्यवहार के विरुद्ध पुरुष) पहल दुर्व्यवहार के पुरुष पीड़ितों को सहायता प्रदान करती है। घरेलू हिंसा, हिरासत और दुर्व्यवहार से जुड़े मामलों में निष्पक्ष उपचार सुनिश्चित करने के लिए लिंग-तटस्थ दृष्टिकोण और पुरुषों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षित करें।

केरल में पुलिस के लिए नियमित संवेदीकरण कार्यशालाओं के परिणामस्वरूप लिंग-आधारित शिकायतों का अधिक संतुलित संचालन हुआ है। संगठनों को समावेशी कार्यस्थल नीतियाँ अपनाने के लिए बाध्य करें जो पितृत्व अवकाश, पुरुषों द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न और मानसिक स्वास्थ्य सहायता जैसे मुद्दों को सम्बोधित करती हैं। स्वीडन की पैतृक अवकाश नीति पिताओं को समान अवकाश प्रदान करती है, जो घर पर साझा पालन-पोषण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है। लैंगिक न्याय के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए पुरुषों के अधिकारों को समान ईमानदारी से सम्बोधित करने की आवश्यकता है। लैंगिक-तटस्थ कानून, मानसिक स्वास्थ्य सहायता में वृद्धि और सामाजिक रूढ़ियों को ख़त्म करने के लिए जागरूकता अभियान महत्त्वपूर्ण क़दम हैं। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, ₹किसी भी जगह अन्याय हर जगह न्याय के लिए ख़तरा है।₹ एक सही मायने में समावेशी प्रणाली सभी लिंगों को ऊपर उठाती है, समाज में निष्पक्षता और सद्भाव को बढ़ावा देती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पात्र महिला लाभार्थियों को 1000/- रुपये प्रति माह हस्तांतरित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना

परिवहन विशेष न्यूज

गोपनीय कैबिनेट मामला

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग (समन्वय शाखा)
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली

परिचालित मदः- कैबिनेट निर्णय संख्या 3169 दिनांक 12.12.2024

विषयः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पात्र महिला लाभार्थियों को 1000/- रुपये प्रति माह हस्तांतरित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना।

निर्णयः मंत्रिपरिषद ने पैरा-3.4 को छोड़कर तथा पैरा-3.2, 3.3 और 3.6 में संशोधनों के साथ कैबिनेट नोट के पैरा-3 (योजना की विशेषताएं) में निहित प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दी, जो इस प्रकार हैः-

3.2 पात्रता मानदंडः

a) 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं।

b) इस कैबिनेट निर्णय की तिथि अर्थात 12.12.2024 को वैध मतदाता पहचान पत्र के साथ एनसीटी दिल्ली की निवासी होनी चाहिए।

3.3 बहिष्करण मानदंडः

a) पूर्व या वर्तमान स्थायी सरकारी कर्मचारी (या तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों में)

b) वर्तमान या पूर्व निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि (सांसद, विधायक या पार्षद)।

c) कोई भी महिला जिसने पिछले मूल्यांकन चक्र में आयकर का भुगतान किया हो।

d) जीएनसीटीडी की तीन सामाजिक सुरक्षा वित्तीय सहायता योजनाओं में से किसी एक की लाभार्थी। विकलांगता पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन और संकटग्रस्त महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना।

3.6 पंजीकरण प्रक्रिया:

योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए, विभाग पंजीकरण और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं (जो पैरा-3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 और 3.12 में निर्धारित किए गए हैं) में किसी भी आगे के संशोधन के लिए संबंधित प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर सकता है।

इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि विभाग परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना सहित योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

-एसडी/-
(धर्मेंद्र)
कैबिनेट सचिव

सं.एफ.53/597/जीएडी/सीएन/2023/डीएसजीएडीआईआईआई/2277-2284
दिनांकः 12.12.2024

1. उपराज्यपाल के प्रधान सचिव, राज निवास, दिल्ली।
2. अपर सचिव। मुख्यमंत्री के सचिव, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. मंत्री (स्वास्थ्य) के सचिव, दिल्ली सरकार।
4. मंत्री (जीएडी) के सचिव, दिल्ली सरकार।
5. मंत्री (खाद्य एवं आपूर्ति) के सचिव, दिल्ली सरकार।
6. मंत्री (श्रम) के सचिव, दिल्ली सरकार।
7. सचिव (डब्ल्यूसीडी), महिला एवं बाल विकास विभाग, जीएनसीटीडी।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, जीएनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली,

7.12.24 (नवीन कुमार चौधरी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (जीएडी)

CONFIDENTIAL
CABINET MATTER

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(CO-ORDINATION BRANCH)
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI

CIRCULATED ITEM

CABINET DECISION NO. 3169 DATED 12.12.2024

Subject: Mukhyamantri Mahila Samman Yojana for transfer of Rs.1000/- per month to eligible women beneficiaries in National Capital Territory of Delhi.

Decision: The Council of Ministers considered and approved the proposals contained in Para-3 (Features of the scheme) of the Cabinet Note except Para-3.4 and with the modifications of Paras - 3.2, 3.3 and 3.6 as under:-

3.2 Eligibility Criteria:
a) Women above 18 years of age.
b) Should be a resident of NCT of Delhi with valid Voter ID Card as on the date of this Cabinet Decision i.e. 12.12.2024.

3.3 Exclusion Criteria:
a) Past or present permanent government employees (either in central government, state government or local bodies)
b) Present or former elected woman public representative (MP, MLA or Councillor).
c) Any woman who has paid Income Tax in the last assessment cycle.
d) Beneficiaries of any of the three social security financial assistance schemes of GNCTD viz. Disability pension scheme, Old age pension and Financial assistance scheme to women in distress.

3.6 Registration Process:
For smooth implementation of the scheme, the Department may obtain approvals for any further modifications in the registration and implementation processes (which have been laid out in Para – 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 and 3.12) from Minister-in-Charge concerned.

Further, the Council of Ministers decided that the Department will take necessary steps for smooth implementation of scheme including setting up of Project Management Unit.

-Sd/-
(Dharmendra)
Secretary to the Cabinet

No.F.53/597/GAD/CN/2023/dsgadiii/ 2277-2284 Dated: 12.12.2024

1. Pr. Secretary to Lt. Governor, Raj Niwas, Delhi.
2. Addl. Secretary to Chief Minister, Delhi Secretariat, New Delhi.
3. Secretary to Minister (Health), Govt. of NCT of Delhi.
4. Secretary to Minister (GAD), Govt. of NCT of Delhi.
5. Secretary to Minister (Food & Supply), Govt. of NCT of Delhi.
6. Secretary to Minister (Labour), Govt. of NCT of Delhi.
7. Secretary (WCD), Women & Child Development Department, GNCTD.
8. Staff Officer to Chief Secretary, GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.

12.12.24
(Navin Kumar Choudhary)
Addl. Chief Secretary (GAD)

दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, AQI 300 के पार; अगले तीन दिनों तक सुधार के आसार नहीं

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़कर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। शाम को एयर इंडेक्स 300 के पार हो गया। सीपीसीबी के अनुसार मौसमी परिस्थितियों के कारण दिल्ली में सोमवार से बुधवार तक तीन दिन हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रह सकती है। इससे ठंड के साथ वायु प्रदूषण भी लोगों को परेशान करेगा।

नई दिल्ली। एनसीआर में रविवार को स्माग व हवा की गति बेहद कम होने के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। इस वजह दिल्ली सहित एनसीआर में ज्यादातर प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। शाम होते-होते दिल्ली में एयर इंडेक्स 300 के पार बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार मौसमी परिस्थितियों के कारण दिल्ली में सोमवार से बुधवार तक तीन दिन हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रह सकती है। इससे ठंड के साथ वायु प्रदूषण भी लोगों को परेशान करेगा।

दिल्ली का औसत एयर इंडेक्स 294 रहा

सीपीसीबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार रविवार को दिल्ली का औसत एयर इंडेक्स 294 रहा जो खराब श्रेणी में उच्च स्तर पर है। एक दिन पहले शनिवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स मध्यम श्रेणी में 193 था। इसके मुकाबले औसत एयर इंडेक्स में 101 अंकों की बढ़ोतरी हुई।

इस माह अब तक आठ दिन हवा की गुणवत्ता खराब

इसका कारण यह है कि सुबह साढ़े पांच बजे से शाम साढ़े पांच बजे के बीच हवा की गति महज चार से आठ किलोमीटर के बीच रही। शाम को हवा की गति और ज्यादा कम हो गई। इस वजह से शाम छह बजे एयर इंडेक्स 303 पहुंच गया। इससे शाम को हवा की गुणवत्ता बेहद श्रेणी में पहुंच गई। दिल्ली में इस माह अब तक आठ दिन हवा की गुणवत्ता खराब, एक दिन बेहद खराब और छह दिन हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही है।

रविवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 228

वहीं स्विस कंपनी के एप आइक्यूएयर ने रविवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 228 बताया, जो सीपीसीबी द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार खराब श्रेणी में माना ताजा है। सीपीसीबी के अनुसार शाम छह बजे दिल्ली के 35 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से 25 जगहों पर एयर इंडेक्स 300 से ज्यादा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया था। इस वजह से वातावरण में पीएम-10 का अधिकतम स्तर 219.3 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर जो सामान्य मानक से दोगुना से ज्यादा है। पीएम-2.5 का स्तर 120.6 माइक्रग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया, जो सामान्य मानक से दोगुना है।

क्या इंदौर की तरह भारत देश की राजधानी दिल्ली को भी भिखारी मुक्त बनाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए ?

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर को अब भिखारी मुक्त शहर बनाने की योजना है। 1 जनवरी, 2025 से इंदौर प्रशासन उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा जो भिखारियों को भीख देंगे।

जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि प्रशासन ने इंदौर में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पहले ही जारी कर दिया है।

इंदौर कलेक्टर ने कहा, ₹भीख मांगने के खिलाफ हमारा जागरूकता अभियान इस महीने (दिसंबर) के अंत तक शहर में चलेगा। अगर कोई व्यक्ति 1 जनवरी से भीख देते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। मैं इंदौर के सभी निवासियों से अपील करता हूं कि वे लोगों को भीख देकर पाप के भागीदार न बनें।"

उन्होंने कहा कि प्रशासन ने हाल के महीनों में लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर करने वाले तमाम गिरोहों का पर्दाफाश किया है और भीख मांगने में शामिल कई लोगों का पुनर्वास भी किया गया है।

बता दें कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश के 10 शहरों को भिखारी मुक्त बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें इंदौर भी शामिल है।

पता हो कि इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमों ने पिछले दिनों 14 भिक्षुओं को पकड़ा था। इस कार्रवाई में राजवाड़ा के शनि मंदिर के पास भीख मांग रही एक महिला के पास से 75 हजार रुपये बरामद हुए थे, जो उसने महज 10-12 दिनों में इकट्ठे किए थे।

परियोजना अधिकारी ने बताया कि शहर में कुछ ऐसे परिवार हैं, जो बार-बार पकड़े जाने के बावजूद भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं। अभियान के तहत इन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।

क्या भारत देश की राजधानी में भी उपराज्यपाल दिल्ली को इस तरह का "भिखारी/भिक्षुक मुक्त" पायलट प्रोजेक्ट लागू नहीं करना चाहिए ?

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: क्या सरकार अब भी सो रही है?

इशिका मुख्य रिपोर्टर न्यूज परिवहन विशेष

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने पूछा है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्तर पर क्यों पहुंच गई है और सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है। यह सवाल उठता है कि क्या सरकार अब भी इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर रही है?

क्या है मामला?

हाल ही में, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 476 तक पहुंच गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अदालत ने यह भी पूछा है कि क्या सरकार ने आपातकालीन योजना तैयार की है और इसे लागू करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं।

सरकार की भूमिका पर सवाल

यहां सवाल उठता है कि जब दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है, तो सरकार अब तक क्या कर रही थी? क्या यह समय की मांग नहीं है कि सरकार तत्काल प्रभाव से ठोस कदम उठाए और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी योजनाएं लागू करे?

दिल्ली की स्थिति

दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। हाल ही में, विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा मिला है। यह स्थिति दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है।

आवश्यक कदम

- आपातकालीन योजना का तुरंत कार्यान्वयनः * सरकार को तुरंत प्रभाव से आपातकालीन योजना लागू करनी चाहिए, जिसमें निर्माण गतिविधियों पर रोक, वाहनों की संख्या में कमी, और पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई शामिल हो।

- सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावाः निजी वाहनों की संख्या कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए।

- *जन जागरूकता अभियानः * लोगों को प्रदूषण के खतरों और बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करना चाहिए।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी यह दर्शाती है कि यह समस्या अब नियंत्रण से बाहर हो रही है। सरकार को तत्काल प्रभाव से ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि दिल्लीवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके। अब देखना यह है कि सरकार इस चेतावनी को गंभीरता से लेकर क्या कदम उठाती है।

रशियन फिल्म फेस्टिवल 2024: मुंबई और दिल्ली में ऐतिहासिक सफलता के साथ हुआ समापन

सुषमा रानी

नई दिल्ली/मुंबई। रशियन फिल्म फेस्टिवल 2024 ने भारत में अपने सफर को 15 दिसंबर को शानदार तरीके से पूरा किया। मुंबई और दिल्ली में आयोजित इस फेस्टिवल ने सिनेमा प्रेमियों और सांस्कृतिक प्रेमियों पर गहरी छाप छोड़ी। यह उत्सव मुंबई के सिनेपोलिस फन रिपब्लिक, अंधेरी में 12 से 15 दिसंबर और दिल्ली के सिनेपोलिस, साकेत में 13 से 15 दिसंबर तक चला। रोस्किनो और रूसी संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस फेस्टिवल की शुरुआत 12 दिसंबर को मुंबई में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुई। इस मौके पर प्रमुख रशियन प्रतिनिधि, रूसी दूतावास के सांस्कृतिक अधिकारी और संस्कृति मंत्रालय के सदस्य मौजूद थे। समारोह का मुख्य आकर्षण मिखाइल लुकाचेव्स्की की फिल्म ₹ट्रायम्फ₹ थी, जिसे दर्शकों ने भरपूर सराहा। फेस्टिवल में दिखाई गई फिल्मों की थीम्स ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। फिल्मों के बाद हुए इंटरएक्टिव सेशन ने दर्शकों को रूसी सिनेमा और उसके विचारों को गहराई से समझने का मौका दिया। मुंबई में सफलता के बाद फेस्टिवल 13 दिसंबर को दिल्ली पहुंचा। सिनेपोलिस, साकेत में माहौल उत्साह से भरा हुआ था। यहां दिखाए गए फिल्म संग्रह में "आइस 3", "द फ्लाइंग शिप", "द पायरेट्स ऑफ द बराकुडा गैलेक्सी" और कालजयी क्लासिक "गेस्ट फ्रॉम द फ्यूचर" जैसी फिल्में शामिल थीं। इन फिल्मों को अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ दिखाया गया ताकि हर कोई इन्हें आसानी से समझ सके। इस फेस्टिवल की खासियत इसका दोस्ताना और पारिवारिक माहौल था, जिसने हर उम्र के दर्शकों को आकर्षित किया। हर शो हाउसफुल रहा, और जब 15 दिसंबर को मुंबई और दिल्ली में फेस्टिवल का समापन हुआ, तो हर दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ फिल्मों को विदाई दे रहा था। समापन समारोह में सिनेमा की ताकत का जश्न मनाया गया, जो भाषाओं और सीमाओं को पार कर अलग-अलग संस्कृतियों को एक साथ लाने में सक्षम है। दर्शकों ने फेस्टिवल की फिल्मों की शानदार क्यूरेशन की सराहना की, जिसने समकालीन और क्लासिक फिल्मों का बेहतरीन मिश्रण प्रस्तुत किया।

ओक्साना फ्रोलोवा, जो रॉस्किनो की डिप्टी डायरेक्टर और रशियन संस्कृति मंत्रालय की प्रतिनिधि हैं, ने भारत में रशियन फिल्मों को प्रदर्शित करने के महत्व पर जोर देते हुए भावुकतापूर्वक बात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच पारस्परिक प्रशंसा को भी रेखांकित किया और कहा कि भारतीय सिनेमा रूसी दर्शकों को लगातार प्रेरित करता रहा है। फ्रोलोवा ने कहा, "भारतीय अभिनेता और फिल्में रशियन जनता के दिलों में एक विशेष स्थान रखती हैं, और ऐसे आयोजन हमारे साझा सांस्कृतिक मूल्यों का उत्सव मनाते हैं, जो हमें एकजुट करते हैं।" रशियन फिल्म फेस्टिवल 2024 केवल एक फिल्म फेस्टिवल नहीं था, यह भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक पुल का प्रतीक था। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर सराहना और समझ को बढ़ावा दिया। जब फेस्टिवल का समापन हुआ, तो दर्शक 2025 के अगले संस्करण का बेसब्री से इंतजार करने लगे। इस ऐतिहासिक सफलता के साथ, रशियन फिल्म फेस्टिवल ने यह साबित कर दिया कि सिनेमा दिलों को जोड़ने और लोगों को प्रेरित करने का सबसे सशक्त माध्यम है।

सुप्रीम कोर्ट की महिला सुरक्षा पर सख्त टिप्पणी: क्या अब भी कुछ नहीं बदला?

इशिका मुख्य रिपोर्टर न्यूज परिवहन विशेष

नई दिल्ली। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या कांड की 12वीं बरसी पर, सुप्रीम कोर्ट ने महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यह सवाल उठता है कि क्या अब भी कुछ नहीं बदला?

क्या है मामला?

सुप्रीम कोर्ट में महिला वकीलों के संगठन 'सुप्रीम कोर्ट वुमन लॉयर्स एसोसिएशन' (SCWLA) ने याचिका दायर कर पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश बनाने की मांग की है। इस याचिका में सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, अश्लील सामग्री पर रोक लगाने और बलात्कार के दोषियों के लिए रासायनिक बधियाकरण जैसे कठोर उपायों की सिफारिश की गई है।

सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने इन मांगों पर विचार करते हुए कहा कि कुछ सुझाव 'क्रूर' और 'कठोर' हैं। हालांकि, अदालत ने यह भी माना कि कुछ पहलुओं पर गहन विचार की आवश्यकता है, जैसे सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा और उचित आचार संहिता का पालन। अदालत ने संबंधित मंत्रालयों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

महिला वकील संघ की चिंताएं

SCWLA की अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि निर्भया से लेकर अभया (कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुई बलात्कार और हत्या की पीड़िता) तक, कुछ नहीं बदला है। उन्होंने छोटे शहरों में यौन शोषण की घटनाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जो अक्सर रिपोर्ट नहीं होतीं। पवनी ने स्कैंडिनेवियाई देशों में अपनाए गए कठोर दंडात्मक उपायों की वकालत की, जैसे रासायनिक बधियाकरण।

सरकार की भूमिका पर सवाल

यहां सवाल उठता है कि जब दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है, तो सरकार अब तक क्या कर रही थी? क्या यह समय की मांग नहीं है कि सरकार तत्काल प्रभाव से ठोस कदम उठाए और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी योजनाएं लागू करे?

दिल्ली की स्थिति

दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। हाल ही में, विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा मिला है। यह स्थिति दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है।

आवश्यक कदम

* आपातकालीन योजना का तुरंत कार्यान्वयनः सरकार को तुरंत प्रभाव से आपातकालीन योजना लागू करनी चाहिए, जिसमें निर्माण गतिविधियों पर रोक, वाहनों की संख्या में कमी, और पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई शामिल हो।

* सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावाः निजी वाहनों की संख्या कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए।

* जन जागरूकता अभियानः लोगों को प्रदूषण के खतरों और बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करना चाहिए।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी यह दर्शाती है कि यह समस्या अब नियंत्रण से बाहर हो रही है। सरकार को तत्काल प्रभाव से ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि दिल्लीवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके। अब देखना यह है कि सरकार इस चेतावनी को गंभीरता से लेकर क्या कदम उठाती है।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में स्कूल की टाइमिंग बदली डीएम ने शीतलहर को लेकर लिया फैसला

गौतमबुद्ध नगर जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट विद्यालय अब सुबह 9 बजे से खुलेंगे। डीएम के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। सर्दी बढ़ने और शीत लहर चलने के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड आईएसई बोर्ड और आईबी बोर्ड के स्कूलों को भी इस निर्देश का पालन करना होगा। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट विद्यालय मंगलवार से सुबह नौ बजे से खुलेंगे। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. धर्मवीर सिंह ने सभी बोर्ड के प्रधानाचार्य को सोमवार को पत्र भेजा है। स्कूलों के समय में बदलाव लगातार सर्दी बढ़ने के कारण लिया गया।

डीआईओएस के मुताबिक, विद्यालयों के खुलने के समय में बदलाव के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार (DM Manish Kumar) वर्मा ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से लगातार सर्दी बढ़ने और आगामी दिनों में शीत लहर (Cold Wave) चलने के आसार के चलते यह निर्देश दिए हैं।

सभी बोर्ड के स्कूल खुलेंगे समय पर

डीआईओएस ने बताया जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिले में संचालित यूपी बोर्ड (UP Boards School) के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के अलावा, सीबीएसई बोर्ड (CBSE Board), आईएसई बोर्ड (ISE Board) और आईबी बोर्ड (IB Board) अंतर्गत संचालित विद्यालयों के जिम्मेदारों को भी पत्र भेजा गया है।

वरना होगी कार्रवाई

उन्होंने बताया निर्देशों का उल्लंघन कर जो विद्यालय खुले मिलेंगे। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अग्रिम आदेशों तक सुबह 9 बजे से ही सभी विद्यालय खुलेंगे।

शिक्षक पर छात्र के साथ मारपीट करने का आरोप, मुकदमा दर्ज

वहीं, कासना कोतवाली क्षेत्र के एक निजी स्कूल में कक्षा सात के छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित स्वजन ने शिक्षक के खिलफ छात्र के साथ गाली-गलौज करने व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गाली गलीज के साथ पीटा

पुलिस के अनुसार, गिरधरपुर गांव का रहने वाला एक बच्चा कस्बे के सेंट जॉर्ज स्कूल में कक्षा सातवीं का छात्र है। उनका बेटा रोजाना की तरह शनिवार को शुक्रवार को स्कूल पढ़ने गया था। शिक्षक हसन ने बिना वजह उसके साथ न केवल गाली-गलौज की, बल्कि उसकी पिटाई कर दी। घर जाकर बच्चे ने सारी बात अपने स्वजन को बताई।

बच्चा काफी डरा और सहमा

बच्चे के गले पर भी निशान है। घटना के बाद से बच्चा काफी डरा व सहमा हुआ है। वह स्कूल जाने से इनकार कर रहा है। कासना कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी।

किसानों के दिल्ली कूच से पहले पुलिस अलर्ट, केएमपी-केजीपी इंटरचेंज पर नाकाबंदी; चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात

परिवहन विशेष न्यूज

किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान के मद्देनजर पलवल पुलिस अलर्ट पर है। केएमपी-केजीपी इंटरचेंज पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही है। किसान नेताओं ने शम्भू बॉर्डर पर किसानों को रोके जाने पर रोष जताया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से किसानों के लंबित मुद्दों का समाधान करने की मांग की है।

पलवल। किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान को लेकर जिला पुलिस अलर्ट पर है। एक साल तक अटोहां चौक पर चले किसान आंदोलन की जगह नाके लाकर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं केएमपी-केजीपी इंटरचेंज पर नाकाबंदी शुरू कर वाहनों की जांच जारी है। नाके पर पुलिस पलवल में प्रवेश करने वाले वाहनों पर नजर बनाए हुए हैं।

बता दें कि 2020 में तीन कृषि कानूनों के विरोध में देशभर में शुरू हुए किसान आंदोलन में पलवल का केएमपी-केजीपी इंटरचेंज आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा था। ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर दिल्ली जा रहे मध्य प्रदेश के किसानों को पलवल पुलिस ने केएमपी-केजीपी इंटरचेंज पर रोक लिया था।

किसान क्रांति चौक नाम दिया गया

किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर बैठकर धरना शुरू कर दिया था। करीब दो माह तक किसान राष्ट्रीय राजमार्ग पर डटे रहे थे। बाद में मध्य प्रदेश के किसानों को हटाया गया तो स्थानीय किसानों ने दोबारा अटोहां चौक पर धरना शुरू कर दिया और उसे किसान क्रांति चौक नाम दिया गया। करीब एक साल तक किसानों ने धरना जारी रखा था। इस बार किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया तो पुलिस सतर्क हो गई। पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग-19 स्थित केएमपी-केजीपी इंटरचेंज पर नाकाबंदी शुरू कर दी। यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

किसानों को रोके जाने पर किसान नेताओं ने जताया रोष

संयुक्त किसान मोर्चा पलवल ने मंगलवार को शहर की जाट धर्मशाला में बैठक कर सर्वसम्मति से किसानों के लंबित मुद्दों के तत्काल समाधान की मांग की। किसान सभा के जिला प्रधान धर्मचन्द की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मांग की गई कि सरकार लोकतंत्र में आंदोलन के संवैधानिक अधिकार को बहाल रखते हुए शम्भू बॉर्डर पर बैठे किसान संगठनों से बातचीत कर मांगों का समाधान करे।

सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही

बैठक में किसान नेता मास्टर महेंद्र सिंह चौहान व धर्मचंद ने बताया कि किसानों के लंबे संघर्ष के बाद केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों को वापस लेते समय देश के अन्नदाताओं से जो वादे किए गए थे, उन्हें आज तक भी लागू नहीं किया गया है। उल्टे किसानों की मांगों को लेकर देश व प्रदेश की सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि पहले सरकार कह रही थी कि किसान दिल्ली ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर क्यों जाते हैं वो बिना वाहन के दिल्ली क्यों नहीं जाते। अब किसान पैदल दिल्ली जाना चाहते हैं तो उन्हें पैदल भी नहीं जाने दे रहे। सरकार यह बताए कि वह फसल के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रही है।

न्यू नोएडा परियोजना: 15 गांवों की भूमि अधिग्रहण से किसानों की किस्मत बदलेगी या समस्याएं बढ़ेंगी?

इशिका मुख्य रिपोर्टर न्यूज परिवहन विशेष

उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा प्राधिकरण ने न्यू नोएडा को एक अत्याधुनिक औद्योगिक और संस्थागत हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इस परियोजना के पहले चरण में दादरी-नोएडा-गाजियाबाद (DNGIR) क्षेत्र के 15 गांवों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना में हजारों करोड़ रुपये की औद्योगिक इकाइयां, शैक्षणिक संस्थान, और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

किसानों की भूमि अधिग्रहण: लाभ या चुनौती?

न्यू नोएडा के विकास के लिए जिन 15 गांवों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी, वे हैं:

1. भरना
2. बेरंगपुर उर्फ नई बस्ती
3. चीरसी
4. फूलपुर
5. छयासा
6. दयानगर
7. देवटा
8. खण्डेरा गिरजापुर
9. कोट
10. मिल्क खण्डेरा
11. नगला चमरू
12. नगला नैनसुख
13. आनंदपुर
14. राजपुर कलां
15. शाहपुर खुर्द

नोएडा प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित किया है कि अधिग्रहित भूमि के बदले किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा, कुछ किसानों को भूमि अधिग्रहण नीति के तहत विकसित प्लॉट भी दिए जाएंगे।

औद्योगिक इकाइयां और मेडिकल कॉलेज: क्षेत्र का विकास या विस्थापन?

नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक, न्यू नोएडा की भूमि पर औद्योगिक इकाइयां, संस्थागत मेडिकल कॉलेज, और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना है, बल्कि इसे देश के सबसे बड़े औद्योगिक हब में बदलना भी है। यह योजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी बल प्रदान करेगी।

किसानों की उम्मीदें और चिंताएं

जिन गांवों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी, उनके किसानों को उम्मीद है कि यह योजना उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। कई किसान इस मुआवजे से बड़े कारोबारी बनने की योजना बना रहे हैं, जबकि कुछ अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रियाएं

स्थानीय निवासियों और व्यापारिक समुदाय में न्यू नोएडा परियोजना को लेकर काफी उत्साह है। उन्हें उम्मीद है कि यह परियोजना पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। निवासियों को बेहतर सड़कें, शिक्षा संस्थान, और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की भी उम्मीद है। इस परियोजना से जुड़ी विकास गतिविधियों से क्षेत्र में जमीन की कीमतें भी तेजी से बढ़ने की संभावना है।

अधिकारियों की प्राथमिकता: पारदर्शिता और तेज प्रक्रिया

नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। किसानों को उनकी सहमति से जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिग्रहण प्रक्रिया से किसानों को कोई नुकसान न हो। न्यू नोएडा परियोजना पूरे क्षेत्र के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगी।"

भविष्य की संभावनाएं:

न्यू नोएडा को देश का सबसे उन्नत औद्योगिक और संस्थागत क्षेत्र बनाने की योजना है। इस परियोजना के तहत:

- हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा।
- क्षेत्र में स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा।
- न्यू नोएडा आने वाले समय में उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक और शैक्षिक केंद्र बन सकता है।

यह परियोजना विकास की नई कहानी लिखने जा रही है। रफ्तार टुडे पर बने रहें और न्यू नोएडा से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाएं।

यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई दिशा देने की क्षमता रखती है, लेकिन किसानों की चिंताओं और उनकी भूमि के उचित मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा।

भारतीय मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन 13-15 दिसंबर 2024 का आगाज़-विज़न 2047 की टीम इंडिया का मंथन

विज़न 2047 के लिए प्रत्येक भारतीय की जन-भागीदारी से ही टीम इंडिया सफ़ल होगी
मुख्य सचिवों रूपी टीम इंडिया का खुले दिमाग से चर्चा के लिए एक साथ आना,विज़न 2047 के लिए मील का पत्थर साबित होगा-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर जिस तेजी के साथ भारत प्रौद्योगिकी, विज्ञान, स्पेस सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से नए इनोवेशन व नवाचार सृजित कर आगे बढ़ रहा है उसे देखकर दुनियाँ हैरान है व समझ गई है कि भारत अपने लक्ष्य विज़न 2047 की डेड लाइन से पहले ही पूरा कर लेगा व विकसित भारत बन विश्व की नंबर एक अर्थव्यवस्था बन जाएगा,जिससे विश्वगुरु का दर्जा पाने से कोई नहीं रोक सकता, जिसका पहिया लग चुका है व तेजी से रणनीतियां बनाकर क्रियान्वयन किया जा रहा है उसी कड़ी में दिनांक 13-15 दिसंबर 2024 को भारत के विभिन्न मंत्रालय के मुख्य सचिवों क़े चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन 15 दिसंबर 2024 को माननीय पीएम के संबोधन से हुआ जिसमें सम्मेलन में मुख्य रूप से जिन व्यापक विषयों पर चर्चा की उसके अंतर्गत छह क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया,विनिर्माण, सेवा, ग्रामीण गैर-कृषि, शहरी, नवीकरणीय ऊर्जा और परिपत्र अर्थव्यवस्था को चिन्हित किया गया है।विकसित भारत के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास केंद्रों के रूप में शहरों का विकास, निवेश के लिए राज्यों में आर्थिक सुधार और मिशन कर्मयोगी के माध्यम से क्षमता निर्माण पर चार विशेष सत्र भी किए। इसके अलावा, भोजन के दौरान कृषि में आत्मनिर्भरता: खाद्य तेल और दालें, वृद्ध आबादी के लिए देखभाल अर्थव्यवस्था, पीएम सूर्य घर: निःशुल्क बिजली योजना कार्यान्वयन और भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित विचार- विमर्श किया।सम्मेलन में प्रत्येक विषय के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को भी प्रस्तुत किया,ताकि राज्यों में पारस्परिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सके। सम्मेलन में सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव,वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्र विशेषज्ञ तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे चूँकि मुख्य सचिव रूपी टीम इंडिया का मंथन हुआ, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी क़े सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, मुख्य सचिवों रूपी टीम इंडिया का खुले दिमाग से चर्चा के लिए एक साथ आना विज़न 2047 के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

साथियों बात अगर हम भारत के मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन 13-15 दिसंबर 2024 के आगाज़ की करें तो,केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और अधिक बढ़ावा देने की दिशा में यह एक और महत्वपूर्ण कदम हुआ इस सम्मेलन में राज्यों के साथ साझेदारी में एक साझा विकास एजेंडा और सुसंगत कार्रवाई के लिए प्रारूप तैयार करने और उसे लागू करने पर बल दिया।यह उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल पहलों को बढ़ाने और ग्रामीण एवं शहरी दोनों आबादी के लिए स्थायी रोजगार के अवसरों का सृजन करते हुए भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने हेतु सहयोगी कार्रवाई के लिए आधार तैयार करेगा।सम्मेलन में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, नीति आयोग, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और क्षेत्र विशेषज्ञों के बीच व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर, चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना-जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना विषय पर केंद्रित था, जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनुसरण करने हेतु सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और रणनीतियों को शामिल किया।

साथियों बात अगर हम माननीय पीएम द्वारा मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन को 15 दिसंबर 2024 की शाम समापन संबोधन की करें तो, रविवार को राज्यों से कहा कि वे ऐसा वातावरण बनाएं जहां स्टार्ट-अप्स आसानी से बढ़ सकें, साथ ही सरकारी नियमों को सरल बनाएं, जो आम नागरिकों के लिए अक्सर कठिन होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को शासन के तरीके में सुधार करना चाहिए ताकि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी बढ़ सके। सुधार प्रदर्शन और बदलाव पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है और लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना भी जरूरी है।स्वास्थ्य क्षेत्रपर पीएम ने कहा कि मोटापा देश के लिए बड़ी चुनौती बन गया है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उनका मानना था कि एक फिट और स्वस्थ भारत ही विकसित भारत बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को 2025 तक तपेदिक (टीबी) मुक्त किया जा सकता है और इस लक्ष्य में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का अहम रोल होगा।उन्होंने कहा कि भारत की पुरानी पांडुलिपियां हमारी धरोहर हैं और राज्यों को इन्हें डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए।राज्यों से कहा कि वे छोटे शहरों में ऐसे स्थानों की पहचान करें, जहां उद्यमी बैंकिंग, रसद और अन्य सेवाओं का फायदा उठा सकें। उन्होंने ई-कचरे के पुनर्चक्रण की जरूरत पर भी बात की, क्योंकि डिजिटल समाज बढ़ने से यह समस्या और बड़ी हो सकती है।शहरों को आर्थिक विकास का केंद्र बनाने के लिए मानव संसाधन विकास पर काम करना चाहिए, और शहरी शासन, जल प्रबंधन और पर्यावरण के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले संस्थान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ती शहरीकरण के साथ, हमें शहरी आवास की समस्या पर भी ध्यान देना होगा। यह सम्मेलन विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें यह बात भी सामने आई कि महिलाओं के नेतृत्व में होने वाले विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिल सकता है।सम्मेलन यह दर्शाता है कि भारत को मध्यम आय वाले से उच्च आय वाले देशों में बदलने के लिए उद्यमिता, कौशल और रोजगार के नए अवसरों पर काम करना जरूरी है,और इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।विशेष रूप से टियर 2/3शहरों में स्टार्ट-अप की तारीफ की, उन्होंने राज्यों से ऐसे इनोवेशन को प्रोत्साहित करने और ऐसा माहौल देने करने की दिशा में काम करने को कहा,जहां स्टार्ट- अप को मदद मिल सकें. उन्होंने राज्यों से छोटे शहरों में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सही जगह की पहचान करने और उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने, लॉजिस्टिक्स और सुविधा प्रदान करने की पहल करने की अपील की। राज्यों को जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए शासन मॉडल में सुधार करना चाहिए।उन्होंने यह भी कहा कि इंफ्रूवमेंट परफॉर्मेंस और चेंज पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है और लोगों को सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी देना भी जरुरी है। सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बात करते हुए पीएम ने कहा कि गोबर्धन कार्यक्रम को अब एक बड़े ऊर्जा संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। ब्लॉकों और जिलों में तैनात सक्षम अधिकारी जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकते हैं. उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा सामाजिक -आर्थिक लाभ भी होगा. पीएम मोदी ने अधिकारियों को शहरों को आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मानव संसाधन विकास के लिए काम करने के लिए भीप्रोत्साहित किया।उन्होंने शहरी प्रशासन, जल और पर्यावरण प्रबंधन में स्पेशलाइजेशन के लिएइंस्टिट्यूट विकसित करने पर जोर दिया, बढ़ती शहरी गतिशीलता के साथ, उन्होंने पर्याप्त शहरी आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया, जिससे नए इंडस्ट्रियल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहतर प्रोडक्टिविटी होगी।उन्होंने कहा, जिस तरह सभी क्षेत्रों के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने अलग- अलग परिस्थितियों, वैचारिक मतभेदों और अलग- अलग तरीकों के बावजूद स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उसी तरह प्रत्येक भारतीय को 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करना चाहिए।

अतः अगर हम उपलब्ध पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारतीय मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन 13-15 दिसंबर 2024 का आगाज़-विज़न 2047की टीम इंडिया का मंथनविज़न 2047 के लिए प्रत्येक भारतीय की जन-भागीदारी से ही टीम इंडिया सफ़ल होगी।मुख्य सचिवों रूपी टीम इंडिया का खुले दिमाग से चर्चा के लिए एक साथ आना, विज़न 2047 के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो को लेकर ताजा अपडेट, 24 किलोमीटर रूट पर बनेंगे 10 स्टेशन

बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो विस्तार की मांग पूरी होने जा रही है। इस परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) पर काम शुरू हो गया है। छह महीने में डीपीआर तैयार हो जाएगी। इसमें मेट्रो रूट के दौरान स्टेशन बनाने का पूरा जिक्र होगा। कितने पिलर लगाए जाएंगे और आई गाडर लगेंगे इस बारे में भी जानकारी होगी।

फरीदाबाद। बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो का विस्तार करने को लेकर एक और कदम बढ़ा दिया गया है। इस परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) पर काम शुरू हो गया है। छह महीने में डीपीआर तैयार हो जाएगी। इसमें मेट्रो रूट के दौरान स्टेशन बनाने का पूरा जिक्र होगा। कितने पिलर लगाए जाएंगे और आई गाडर लगेंगे, इस बारे में भी जानकारी होगी। पता चला है कि पलवल मेट्रो को कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे और हरियाणा आर्बिटल रेल से जोड़ने की योजना है। बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की मांग कई साल से उठ रही थी।

मनोहर लाल ने की मेट्रो विस्तार की घोषणा

16 अगस्त 2022 को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पृथला विधानसभा क्षेत्र में हुई रैली में मेट्रो के पलवल तक विस्तार की घोषणा की थी। घोषणा के तुरंत बाद संबंधित विभागों ने योजना को अमलीजामा पहनाने का काम शुरू कर दिया। तकनीकी टीम ने बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन से पलवल तक दौरा किया। परियोजना के बीच आ रहे निर्माण और खाली जगह की जांच की गई।

24 किलोमीटर रूट, 10 बनेंगे स्टेशन

कारिडोर की कुल लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है। इस दौरान 10 स्टेशन प्रस्तावित है। इनमें बल्लभगढ़ के बाद पहला स्टेशन सेक्टर 58-59, सीकरी, सोफ्ता, पृथला, बघौला, आल्हापुर और अंतिम पलवल होगा, जो यहां के औद्योगिक क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। बीच में कुछ और स्टेशन बनाए जाएंगे। यह रूट पूरा एलिवेटेड होगा और इस पर 180 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की अनुमानित लागत आने की संभावना है। परियोजना का कुल बजट 4320 करोड़ रुपये आंका गया है।

आमजन व उद्योगों को मिलेगी राहत

बल्लभगढ़ से पलवल के बीच काफी औद्योगिक इकाईयां भी हैं। सबसे अधिक पृथला औद्योगिक क्षेत्र में है। इन सभी को मेट्रो के आगमन से लाभ होगा। पलवल से बल्लभगढ़ व आगे दिल्ली तक रोज दो लाख से अधिक लोग आवागमन करते हैं। फिलहाल लोग रेल व सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं। इसमें कई दिक्कत आती हैं। औद्योगिक इकाईयों में काम करने वाले श्रमिक भी आने-जाने में परेशानी महसूस करते हैं। मेट्रो इन सभी की राह को सुगम कर देगी।

बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री एवं विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि मेट्रो विस्तार के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। इसके तैयार होने के बाद ही कुछ कहा जाएगा कि धरातल पर काम कब तक शुरू हो जाएगा। वैसे उम्मीद है कि अगले साल यह काम शुरू हो जाएगा।

- :सौजन्य :-
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

इस हफ्ते में लॉन्च होगी नई SUV, मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स, होगा नेक्सॉन से लेकर Kylaq से मुकाबला

परिवहन विशेष न्यूज

किआ की ओर से इस हफ्ते भारतीय बाजार में नई एसयूवी को लॉन्च कर दिया जाएगा। कंपनी की ओर से इसमें कई बेहतरीन फीचर्स को दिया जाएगा। जिसमें फ्लश डोर हैंडल सनरूफ एलईडी लाइट्स सहित कई फीचर शामिल हैं। लॉन्च से पहले एक और टीजर सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। इसमें किस तरह की जानकारी सामने आई है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। साउथ कोरियाई वाहन निर्माता Kia की ओर से भारतीय बाजार में कई बेहतरीन वाहनों की बिक्री की जाती है। कंपनी देश में अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए एक और नई गाड़ी को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस हफ्ते लॉन्च होने वाली नई गाड़ी के तौर पर किसे लाया जाएगा। इसमें किस तरह के फीचर्स को ऑफर किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं

लॉन्च होगी नई एसयूवी

Kia Syros SUV के तौर पर भारतीय बाजार में जल्द ही नई गाड़ी को लॉन्च कर दिया जाएगा। इस हफ्ते में गुरूवार को नई गाड़ी को भारत लाया जाएगा। इसमें कई बेहतरीन फीचर्स के साथ ही दमदार इंजन के विकल्प दिए जा सकते हैं।

नए टीजर में मिली यह जानकारी

लॉन्च से पहले सोशल मीडिया पर कंपनी की ओर से कई टीजर जारी किए गए हैं। जिनमें गाड़ी के डिजाइन के साथ ही फीचर्स की काफी जानकारी मिल चुकी है। हाल में ही एक और टीजर को जारी किया गया है जिसमें गाड़ी के कुछ और फीचर्स की जानकारी सामने आई है। इसमें एलईडी लाइट्स, एलईडी डीआरएल, रूफ रेल, एलईडी टेल लाइट्स, फ्लश डोर हैंडल और साइड प्रोफाइल की जानकारी मिली है।

कैसे होंगे फीचर्स

पहले जारी हो चुके टीजर में भी इसके एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक की जानकारी सामने आ चुकी है। कंपनी की ओर से लाई जाने वाली साइरोस एसयूवी का इंटीरियर भी काफी बेहतरीन होगा। इसकी रियर सीट को भी इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे सफर के दौरान ज्यादा आराम मिल सके। साथ ही इसमें सिंगल टोन इंटीरियर को दिया जा सकता है जिसके साथ एंबिएंट लाइट्स, रियर एसी वेंट्स, चार्जिंग पोर्ट, वायरलैस चार्जिंग, एयर प्यूरीफायर, 360 डिग्री कैमरा, ADAS जैसे फीचर्स को दिया जाएगा।

कितना दमदार होगा इंजन

आधिकारिक तौर पर इसके इंजन के बारे में जानकारी तो लॉन्च के समय ही मिल पाएगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसमें दो इंजन के विकल्प दिए जा सकते हैं। जिनमें एक इंजन 1.2 लीटर की क्षमता का होगा और दूसरे इंजन के तौर पर टर्बो का विकल्प दिया जा सकता है।

किनसे होगा मुकाबला

भारतीय बाजार में इसे Compact SUV सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में इसका सीधा मुकाबला अपनी ही कंपनी की Kia Sonet, Mahindra XUV 3XO, Maruti Brezza, Tata Nexon, Hyundai Venue, Nissan Magnite, Renault Kiger जैसी एसयूवी के साथ होगा।

ह्यूंडई Ioniq 9 होगी भारत मोबिलिटी 2025 में पेश

बेहतरीन फीचर्स के साथ मिलेगी 600 किमी. से ज्यादा की रेंज

परिवहन विशेष न्यूज

साउथ कोरियाई वाहन निर्माता Hyundai की ओर से कई बेहतरीन कारों और एसयूवी को भारतीय बाजार में ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से Bharat Mobility 2025 में भी कुछ बेहतरीन वाहनों को पेश किया जाएगा। जिनमें Hyundai Ioniq9 भी शामिल होगी। इसमें किस तरह के फीचर्स दिए जाते हैं। सिंगल चार्ज में कितनी दूरी तय की जा सकती है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में जनवरी 2025 में Bharat Mobility 2025 का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान देश और दुनिया की कई प्रमुख वाहन निर्माताओं की ओर से अपनी अपनी कारों और एसयूवी को पेश और लॉन्च किया जाएगा। इसी क्रम में साउथ कोरियाई वाहन निर्माता Hyundai भी Ioniq 9 को पेश कर सकती है। कंपनी की इस गाड़ी में किस तरह के फीचर्स ऑफर किए जाते हैं और सिंगल चार्ज में कितने किलोमीटर तक इसे चलाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

पेश होगी Hyundai Ioniq9 EV

हुंडई की ओर से भारत में इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर Hyundai Ioniq9 को पेश किया जा सकता है। अभी कंपनी ने इस बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे जनवरी में होने वाले Bharat Mobility 2025 में पेश (Hyundai Ioniq 9 launch) किया जाएगा।

कैसे हैं फीचर्स

Hyundai Ioniq9 को कंपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर पेश करेगी। इसमें छह और सात सीटों का विकल्प दिया जाता है। जिसमें पहली दो रो में मसाज जैसे फीचर को दिया गया है। इसके अलावा इसमें सेकेंड रो की सीट को 180 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। इसमें एडजस्टेबल कंसोल, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट, 620 लीटर का लगेज रूम, पैनोरमिक सनरूफ, एलईडी लाइट्स, एलईडी डीआरएल, 12 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन,12 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक कर्व्ड डिस्प्ले, एंबिएंट लाइट्स, रूफ-माउंटेड एयर वेंट, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, तीनों पंक्तियों में 100W USB-C पोर्ट और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम के साथ ही 14 स्पीकर वाले बोस सिस्टम का विकल्प भी मिलता है।

कितनी है सुरक्षित

हुंडई की आयोनिक9 इलेक्ट्रिक एसयूवी को काफी सुरक्षित एसयूवी के तौर पर बनाया गया है। इसमें 10 एयरबैग, ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर्स समेत तीसरी पंक्ति के यात्रियों के लिए सीट बेल्ट प्री-टेंशनर और लोड लिमिटर जैसे कुछ सेफ्टी फीचर्स को दिया गया है।

बैटरी और मोटर

110.3 kWh का बैटरी पैक दिया गया है। यह फुल चार्ज होने के बाद 620 किमी तक की रेंज (600 KM range EV) मिलेगी। इसमें छोटे 19-इंच के पहिए दिए गए हैं। यह हुंडई के E-GMP आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। यह 350kW चार्जर के साथ 24 मिनट में 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है। इसमें 400V और 800V चार्जिंग कैपेसिटी दी गई है। इसमें वाहन-से-लोड (V2L) फीचर दिया गया है, जो किसी दूसरे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स या एक्सेसरीज को चार्ज कर सकता है। इसमें लगी मोटर से इसे 218 hp की पावर और 350 Nm का टॉर्क मिलता है।

4 मीटर से छोटी SUV या कॉम्पेक्ट सिडान.. दो नई गाड़ियां एक नई सोच

भारतीय बाजार में November 2024 में दो नई कारों को लॉन्च किया गया है। जिनमें से एक Compact SUV सेगमेंट में पेश की गई है और दूसरी गाड़ी को Compact Sedan सेगमेंट में लाया गया है। एक जैसी कीमत वाली इन कारों में से किस गाड़ी को खरीदना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। नवंबर का महीना भारत की वाहन निर्माताओं के लिए काफी खास है। इस महीने में यूरोप की वाहन निर्माता Skoda के अलावा Maruti की ओर से भी नई गाड़ी को लॉन्च किया गया है। स्कोडा की Kylaq SUV और Maruti Dzire के बीच किसे खरीदना आपके लिए बेहतर (Skoda Kylaq Vs Maruti Dzire) हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Compact सेगमेंट में लॉन्च हुई दो गाड़ियां

देश में बड़ी संख्या में लोग कॉम्पैक्ट सेगमेंट के वाहनों को पसंद करते हैं। जिसे देखते हुए कंपनियों की ओर से भी इस सेगमेंट में कई वाहनों को लाया जाता है। बीते महीने के दौरान ही देश में दो नई गाड़ियों को लॉन्च किया गया है। जिनमें Compact SUV और Compact Sedan शामिल हैं। Skoda Kylaq को SUV और Maruti Dzire को Sedan के तौर पर लाया गया है।

Skoda Kylaq Vs Maruti Dzire Features

Skoda Kylaq में कंपनी की ओर से कुछ बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। शाइनी ब्लैक फ्रंट ग्रिल, 17 इंच अलॉय व्हील्स, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लाइट्स, ड्राइवर और को-ड्राइवर की 6वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट्स, सिंगल पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ, 20.32 सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलैस चार्जिंग, 25.6 सेमी इंफोटनेमेंट सिस्टम, ट्रंक में तीन किलोग्राम की क्षमता का हुक जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं।

वहीं Maruti Dzire 2024 में 15 इंच के अलॉय व्हील्स, एलईडी डीआरएल, एलईडी लाइट्स, एलईडी फॉग लैंप, बॉडी कलर्ड बंपर, हाई माउंट एलईडी स्टॉप लैंप, शॉर्क फिन एंटीना, फ्रंट फुटवैल इलुमिनेशन, लैदर रैप स्टेयरिंग व्हील, ड्यूल टोन इंटीरियर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 360 डिग्री व्यू कैमरा, टीपीएमएस, सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, वायरलैस चार्जर, पुश बटन स्टॉर्ट/स्टॉप, ऑटो हैडलैंप, रियर एसी वेंट, डिजिटल एसी पैनल, सुजुकी कनेक्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Skoda Kylaq Vs Maruti Dzire Engine

Skoda Kylaq में एक लीटर की क्षमता का टीएसआई इंजन दिया है। जिससे इसे 85 किलोवाट की पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 6स्पीड मैनुअल और डीसीटी ट्रांसमिशन के विकल्प को दिया गया है।

स्टीलवर्ड ने लॉन्च की नई विंटेज सीरीज, क्लासिक स्टाइल में मिलेंगे सुरक्षित हेलमेट, कीमत 959 रुपये से शुरू

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में हर साल बड़ी संख्या में दो पहिया वाहन चालक हेलमेट न लगाने के कारण गंभीर हादसों का शिकार हो जाते हैं। सुरक्षित सफर के लिए भारत की हेलमेट निर्माता Steelbird की ओर से Vintage Series वाले हेलमेट लॉन्च किए गए हैं। किस तरह के डिजाइन स्टाइल और कीमत पर इन हेलमेट्स को खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं।

लॉन्च हुए Steelbird Vintage Series हेलमेट

नई दिल्ली। हेलमेट निर्माता Steelbird की ओर से भारतीय बाजार में Vintage Series के नए हेलमेट्स को लॉन्च किया गया है। इस सीरीज वाले हेलमेट्स को किस कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसमें किस तरह की खासियत दी गई है और यह कितना सुरक्षित होगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्च हुई नई हेलमेट सीरीज

Steelbird की ओर से भारतीय बाजार में नए Vintage Series के नाम से नए Helmets को लॉन्च (Steel Bird Vintage Series helmets) किया गया है। इसे खासतौर पर ऐसे राइडर्स के लिए लाया गया है जिनको सुरक्षा के साथ ही स्टाइल पसंद आता है।

क्या है खासियत

कंपनी की ओर से इस हेलमेट को बनाने में थर्मोप्लास्टिक शेल का इस्तेमाल किया गया है, जो बेहतर इम्पैक्ट रेसिस्टेंस प्रदान करता है और साथ ही हल्का भी है। हाई डेंसिटी एक्सपैंडेड पोलिस्टाइरीन के कारण यह सफर के दौरान लगने वाले झटकों को ज्यादा अच्छी तरह से सोख लेता है, जिस कारण राइडर की सुरक्षा में बढ़ोतरी हो जाती है। इसके साथ ही इनमें पीछे की ओर लेदर स्ट्रैप को दिया गया है जिससे हेलमेट को विंटेज लुक मिलता है। हाफ फेस हेलमेट होने के कारण इनमें बेहतर वेंटिलेशन मिलती है।

कितना है सुरक्षित

कंपनी की ओर से इस हेलमेट को काफी सुरक्षित बनाया गया है। इसे DOT (FMVSS No. 218) और BIS (IS 4151:2015) सेफ्टी नॉर्म्स पर सर्टिफाइड किया गया है। जिससे इसे देश के साथ ही विदेशों में स्टाइल के साथ सुरक्षित राइड का भरोसा मिलता है।

कंपनी के अधिकारियों ने कही यह बात

स्टीलबर्ड हेलमेट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव कपूर ने कहा कि भारत में हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और 19 लोगों की जान जाती है। इन हादसों में से 45 फीसदी दुर्घटनाएं दोपहिया वाहनों से जुड़ी होती हैं। ऐसे में राइडर्स के लिए यह जरूरी है कि वे सुरक्षा को प्राथमिकता दें और स्टाइल के साथ कोई समझौता न करें। हमारी एसबीएच विंटेज सीरीज़ के साथ, हम ऐसे हेलमेट्स प्रदान करना चाहते हैं जो न केवल ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरें, बल्कि राइडर्स को एक अलग और आरामदायक डिज़ाइन भी प्रदान करें।

रंग और साइज

Steelbird की ओर से नए हेलमेट की सीरीज में कुल तीन हेलमेट लाए गए हैं, जिनमें एसबीएच-54, एसबीएच-55 और एसबीएच-56 शामिल हैं। इनको कई रंगों और साइज में लाया गया है। इसमें तीन साइज ऑफर किए गए हैं, जिसमें 580mm, 600mm और 620mm शामिल हैं।

भारत को 2030 तक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग मांग को पूरा करने के लिए ₹16,000 करोड़ के पूंजीगत व्यय की जरूरत

परिवहन विशेष न्यूज

भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए देश की बढ़ती सार्वजनिक चार्जिंग मांग को पूरा करने और 2030 तक 30 प्रतिशत से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन (विद्युतीकरण) के मिशन को हासिल करने के लिए 16,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की जरूरत है।

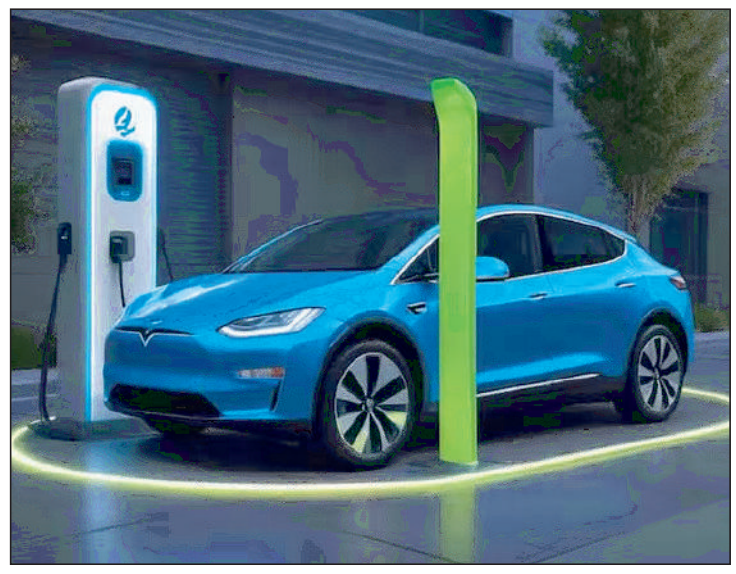

नई दिल्ली। भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए देश की बढ़ती सार्वजनिक चार्जिंग मांग को पूरा करने और 2030 तक 30 प्रतिशत से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन (विद्युतीकरण) के मिशन को हासिल करने के लिए 16,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की जरूरत है। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

"इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: 2030 रोडमैप₹ पर फिक्की की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए मौजूदा वित्तीय व्यवहार्यता 2 प्रतिशत से भी कम उपयोग दर के साथ कम बनी हुई है। और लाभप्रदता और मापनीयता हासिल करने के लिए, ₹हमें 2030 तक 8-10 प्रतिशत उपयोग का लक्ष्य रखना होगा।"

फिक्की ने कहा, "उदाहरण के लिए, ऊर्जा खपत की परवाह किए बिना निश्चित शुल्क के साथ बिजली शुल्क की वर्तमान लागत संरचना और सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर कम उपयोग के कारण लाभ-हानि लक्ष्य हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों में कोई/कम निश्चित शुल्क नहीं है। लेकिन ऐसे अन्य राज्य भी हैं जहां निश्चित शुल्क ज्यादा हैं, जिससे व्यवहार्यता चुनौतीपूर्ण है।"

रिपोर्ट में भारत को स्वच्छ ऊर्जा और स्थिरता की ओर ले जाने के लिए नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और सरकारी निकायों सहित प्रमुख हितधारकों से कार्रवाई करने का आह्वान किया गया है।

इसमें पांच प्रमुख चुनौतियों को भी रेखांकित किया गया है, जिन्हें सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए संबोधित करने की जरूरत है। इनमें सीमित वित्तीय व्यवहार्यता; डिस्कॉम या बिजली से संबंधित मुद्दे; भूमि से संबंधित मुद्दे; परिचालन संबंधी चुनौतियां; और मानकीकरण और अंतर-संचालन शामिल हैं।

रिपोर्ट में आगे सुझाव दिया गया है कि ईवी चार्जिंग सर्विस के लिए जीएसटी दरों को ईवी वैल्यू चेन में टैक्स के अनुरूप 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक मानकीकृत किया जाना चाहिए। इसने राज्यों में एक समान मूल्य निर्धारण के साथ दो-भाग टैरिफ से एकल-भाग टैरिफ में बदलाव का भी आह्वान किया।

रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि राज्य इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (E3W) को अपनाने को बढ़ावा दें। जैसे कि E3W खरीदने के लिए परमिट की जरूरत नहीं है; अंतरिम में, CNG थ्री-व्हीलर से E3W में स्थानांतरित होने के लिए उसी परमिट का उपयोग करें।

इसने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रोडमैप कार्यान्वयन को सक्षम और निगरानी करने के लिए उद्योग हितधारकों, राज्य और केंद्रीय प्राधिकरणों के प्रतिनिधित्व के साथ एक राज्य-स्तरीय सेल स्थापित करने का सुझाव दिया।

रिपोर्ट की एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश में कहा गया है कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना। और संचालन के लिए विद्युत मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को राज्य डिस्कॉम (वितरण कंपनियों) के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। ताकि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) की समय पर स्थापना सुनिश्चित की जा सके।

रिपोर्ट में आगे सुझाव दिया गया है कि 2015 से 2023-24 तक ईवी बिक्री के आधार पर, विश्लेषण किए गए 700 से ज्यादा शहरों में से, शीर्ष 40 और 20 राजमार्ग खंडों को सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इन शीर्ष 40 शहरों में अगले 3-5 वर्षों में ईवी पैठ में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मौजूदा ईवी अपनाने की दर और अनुकूल राज्य नीतियों को देखते हुए। इसके अलावा, इन 40 प्राथमिकता वाले शहरों को जोड़ने वाले 20 राजमार्ग खंड वाहनों के ट्रैफिक में 50 प्रतिशत का योगदान करते हैं।

अप्रैल 2019 से मार्च 2024 के बीच हुई 36 लाख EV की बिक्री, टॉप-5 में शामिल हुए कौन से राज्य, कहां सबसे कम मांग

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में प्रदूषण कम करने के साथ ही खर्च कम करने के लिए कई लोग EV को खरीदते हैं। सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि April 2019 से लेकर March 2024 के बीच देशभर में कितने Electric Vehicles की बिक्री हुई है। किन राज यों में सबसे ज यादा EV की मांग है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में ICE वाहनों के मुकाबले EV का अडॉप्शन भले ही कम हो, लेकिन इस सेगमेंट को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। जिसे देखते हुए वाहन निर्माताओं की ओर से बेहतरीन फीचर्स के साथ नई EV को लाया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि April 2019 से लेकर March 2024 के बीच कितने Electric Vehicles की बिक्री देशभर में हुई है। Top-5 में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। दिल्ली का नंबर लिस्ट में किस नंबर (EV sales in India) पर है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

कितनी हुई बिक्री

केंद्र सरकार की ओर से संसद में जानकारी दी गई है कि April 2019 से लेकर March 2024 के बीच पांच सालों में कुल कितने Electric Vehicles की बिक्री हुई है। इसके साथ ही सरकार की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि देश में किस राज्य में इस दौरान कितने इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Cars) की बिक्री की गई है। जानकारी के मुताबिक इस अवधि के दौरान देशभर में कुल 3639617 यूनिट्स EV की बिक्री की गई है।

Top-5 में शामिल ये राज य

बिक्री के मामले में जिन राज्यों में सबसे ज्यादा EV का रजिस्ट्रेशन किया गया है, उनमें यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान हैं। उत्तर प्रदेश में April 2019 से March 2024 के बीच 665247 यूनिट्स ईवी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जहां पर 439358 यूनिट्स ईवी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तीसरे नंबर पर 350810 यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन कर्नाटक में हुआ है। इसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है जहां पर 228850 यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है। Top-5 लिस्ट में पांचवें पायदान पर 233503 यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन के साथ राजस्थान है। वहीं इस लिस्ट में दिल्ली का नंबर सात रहा है। दिल्ली में इस अवधि में कुल 216084 यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है।

इन राज यों में सबसे कम हुआ रजिस्ट्रेशन

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MoRTH की ओर से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक सिक्किम में 2019 से 2024 के बीच एक भी इलेक्ट्रिक वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। इसके अलावा लक्ष्यद्वीप में 19, नगालैंड में 27, अरूणाचल प्रदेश में 42, लद्दाख में 88, अंडमान और निकोबार में 191, दादर नगर हवेली और दमन दीव में 468, मिजोरम में 344, मेघालय में 572, मणिपुर में 1273, हिमाचल प्रदेश में 3043, पुदुचेरी में 5933 यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है।

जलवायु पर बढ़ते संकट के जिम्मेदार

विजय गर्ग

दशकों से चले आ रहे सम्मेलनों के बावजूद जलवायु संकट दूर करने के लिए सभी देशों की हिस्सेदारी और जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। यही वजह काप-29 सम्मेलन में विकासशील देशों की चिंता और नाराजगी भारत ने आवाज दी है। उसने सम्मेलन में वैश्विक आईना दक्षिण देशों का नेतृत्व करके अमीर देशों को दिखाया बहरहाल, बाकू में आयोजित सम्मेलन में लंबी जद्दोजहद के सबसे बड़ी घोषणा 'न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल' रूप में सामने आई।

हाल ही में बाकू में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में गहन वार्ता के बाद, जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने की दिशा में कोई ठोस निर्णय न हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सम्मेलन के अंत में जो हासिल हुआ, उसने यह साबित हुआ कि वादों और वास्तविकता के बीच की खाई आज भी विकसित और विकासशील देशों के बीच बहुत गहरी है। सम्मेलन में जरूर कुछ बड़ी और अहम घोषणाएं हुईं, लेकिन उनसे उम्मीद की जाने वाली तात्कालिक और ठोस कार्रवाई का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। दशकों से चले आ रहे सम्मेलनों के बावजूद जलवायु संकट दूर करने के लिए सभी देशों की हिस्सेदारी और जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। यही वजह काप-29 सम्मेलन में विकासशील देशों की चिंता और नाराजगी भारत ने आवाज दी है। उसने सम्मेलन में वैश्विक आईना दक्षिण देशों का नेतृत्व करके अमीर देशों को दिखाया बहरहाल, बाकू में आयोजित सम्मेलन में लंबी जद्दोजहद के सबसे बड़ी घोषणा 'न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल' रूप में सामने आई। जिसमें अमीर देश 2035 तक 300 बिलियन डालर हर साल योगदान करने के लक्ष्य पर सहमत हुए, लेकिन यह रकम गरीब देशों को बेहद कम लगी और इस पर सवाल उठाया पैंतालीस गरीब देशों के समूह ने इसने काप - 29 के नतीजे को 'विश्वासघात' बताया। उनका कहना था कि यह समझौता न तो वैश्विक ताप पर लगाम लगा सकता है और न ही कमजोर देशों की मदद कर सकता है। ऐसे में यह अहम सवाल है कि अब दस साल बाद क्या स्थिति बनेगी, यह किसे मालूम है। फिर यह वादा वे देश निभाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि अनिवार्यता तत्काल कदम उठाने की है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिणाम अब हम सबके सामने हैं। साफ दिख भी रहे हैं। हैरत है कि यह 2009 में 46 2009 4 44 किए गए 100 बिलियन डालर के लक्ष्य की जगह लेता है, जो अब तक कभी पूरा नहीं हुआ। दरअसल, विकसित और विकासशील देशों के बीच यह मतभेद रहा कि जलवायु संकट में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले अमीर देशों को कितनी मदद देनी चाहिए। वहीं जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को खत्म करने का वादा, जो पिछले साल दुबई में काप- 28 में किया गया था, इस बार के समझौते से हटा दिया गया। इससे साबित होता है कि विकसित देश किस हद तक की लापरवाही कर रहे हैं।

हालांकि, भारत और चीन ने इस लक्ष्य को अस्वीकार्य बताते हुए 500 बिलियन सालाना सार्वजनिक वित्त की मांग की। भारत का कहना है कि विकसित देशों ने अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों से बचने के लिए इस लक्ष्य को 'स्वैच्छिक योगदान' और बहुपक्षीय विकास बैंकों की फंडिंग पर निर्भर बना दिया है। अमीर देश अपनी इस दलील पर अब भी अड़े हुए हैं कि इस कोष में विकासशील देश भी योगदान करें। जाहिर है, पैसा न देने का एक बहाना उन्होंने तैयार कर रखा है। सम्मेलन के दौरान कई महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठे, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल चर्चा के स्तर पर ही सीमित रह गए। 'बाकू प्रेसीडेंसीज कंटीन्युइटी कोएलिशन फार क्लाइमेट एंड हेल्थ' की स्थापना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इस पहल का असर तभी होगा, जब इसे पर्याप्त धन और संसाधन मुहैया कराया जाए। कहना गलत न होगा कि विकसित देशों की ओर से आयोजित अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन दिखावा बन कर रह गया है।

काप- 29 में भारत एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में सामने आया। उसने 'कामन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पांसिबिलिटीज' के सिद्धांत पर जोर दिया, जो विकासशील देशों के साथ न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करता है। भारत का यह रुख दूसरे विकासशील और छोटे द्वीपीय देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह सतही और असमान समाधानों को स्वीकार नहीं करेगा। काप 29 ने बता दिया है कि वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना कठिन । जलवायु वित्त का नया लक्ष्य कागज पर अच्छा दिखता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हकीकत है कि धनी देशों के रवैए के कारण विकासशील देश खुद को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। अपने विकास की कीमत पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने पर सहमत हुए गरीब मुल्क इसके मुकाबले के के लिए अमीर देशों की मदद की तरफ देख रहे हैं। लेकिन अमीर और गरीब मुल्कों के बीच अविश्वास का वातावरण दो दशक बाद भी बना हुआ है। निश्चित रूप से यह स्थिति भविष्य में वैश्विक ताप से निपटने के लिए साझा प्रयासों की संभावना को ही खत्म करेगी।

जलवायु परिवर्तन आज पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। इसको लेकर कई तरह की नकारात्मक भविष्यवाणियां भी की जा चुकी हैं। ज्यादातर ऐसे शोर पश्चिमी देशों से ही उठते रहे हैं, जिन्होंने अपने विकास के लिए प्रकृति के विरुद्ध न जाने कितने ही कदम उठाए हैं और लगातार उठा ही रहे हैं। आज भी कार्बन डाई आक्साइड उत्सर्जन करने वाले देशों में 70 फीसद हिस्सा पश्चिमी देशों का ही है जो विकास की अंधी दौड़ में लगे हैं। जाहिर है, आज धरती पर हो रहे जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि विकसित देश ही हैं। आज जो देश विकसित होने का तमगा लगा कर घूम रहे हैं, हैं, वही देश धरती की वर्तमान स्थिति के लिए दोषी हैं। जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में वैसे तो तमाम प्रतिबद्धताएं जताई जाती हैं, लेकिन उन पर पूरी तरह अमल न होना, हमेशा ही गंभीर चिंता का विषय रहा है। यह सत्य है कि जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने आज एक बड़ी चुनौती भारत सहित पूरी दुनिया का उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। कार्बन उत्सर्जन में अपनी सीमित भूमिका होने के बावजूद इसे रोकने के लिए भारत अपनी ओर काम कर रहा है, लेकिन इस मामले में विकसित देशों में अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपने की प्रवृत्ति आम रही है। बेशक हुआ, पर समस्या को ही बेशक चाकू में जलवायु संकट पर गंभीर की गई। यदि जलवायु वित्त पैकरार को समझने की ईमानदार कोशिश नहीं मंथन गहराई पर सहमति बनती, तो इससे जुड़े मुख्य मुद्दों के समाधान की राह खुलती, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। यह निर्विवाद सत्य कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिए विकासशील देशों को अपने विकास को धीमा करना पड़ेगा।

अब काप - 30, ब्राजील में आयोजित होगा। जाहिर है उससे काफी उम्मीदें हैं। जरूरी है कि भविष्य के सम्मेलनों में खोखले वादों की जगह परिवर्तन कोई दूर का संकट नहीं है, यह एक ठोस कदम उठाए जाएं जलती है, जो हर दिन विकराल होती जा रही। गंभीर और वर्तमान है। काप 29 ने जलवायु संकट को हल करने की दिशा में कुछ कदम जरूर उठाए, लेकिन यह दुनिया को याद दिलाता है कि असली काम अभी बाकी है। यह वक्त है जब दुनिया को साहसिक, न्यायसंगत और तत्काल कार्रवाई करनी होगी, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्थायी भविष्य मिल सके।

परिहास का परिदृश्य

विजय गर्ग

हास्य हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। यह मानवीय संवेदनाओं की सर्वश्रेष्ठ अनुभूतियों में से एक उत्कृष्ट अनुभूति है, जो किसी भी स्वस्थ मन से हंसने वाले व्यक्ति को एक अलग तरह की ऊर्जा देता है । इस लिहाज से शायद इसे अन्य ऊर्जाओं से भिन्न कहा जा सकता है, क्योंकि यह हम मनुष्यों के समाज को मानवीयता का एक और गुण प्रदान करता है । यों हास्य वह धारा है, जो कभी मजाक, कभी व्यंग्य, कभी मुस्कान, तो कभी हल्की-फुल्की बातों का हिस्सा होता है। अगर दर्ज दस्तावेजों या गाथाओं के संदर्भ से इसे समझने की कोशिश करें तो इसकी अपनी एक प्रकृति रही है। हम सभी को पता है कि चाहे बीरबल हो या तेनालीराम या फिर चार्ली चैपलिन और महमूद तक सभी हास्य जीवन के अनोखे पात्र रहे हैं । इनके बारे में पढ़ कर, इन्हें किताबों या फिल्मों में देख कर अनायास ही हमारे होठों पर मुस्कान आ जाती है। साहित्य के अंतर्गत यह काका हाथरसी से लेकर आज के कई युवा कवियों में भी हम इसकी लोकप्रियता को देख सकते हैं। दरअसल, यह एक जानी- मानी विधा है, हमारा संसार है और जीवन को आनंद देने का जरिया भी है। गंभीरता का मुखौटा ओढ़कर इससे बचकर निकलने वालों का जीवन नीरज और स्वादहीन बन जाता है। जैसे रसगुल्ले के लिए चाशनी जरूरी है, वैसे ही जीवन को सही तरीके से जीने के लिए हल्का-फुल्का, लेकिन स्वस्थ हंसी-मजाक होना जरूरी है। देखा जाए तो यह उम्मीद का वह दीया है जो लगातार प्रकाशित रहता है । स्वस्थ रहने के लिए भी हमारा हंसना जरूरी है, चाहे हम कितना भी कहें कि जीवन कोई फिल्म का हिस्सा नहीं है, इसे थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। मगर ऐसा मानना अपने आप को सरलता से दूर ले जाने की तरह है। हमारे सहज मन को हंसी और खुशी की आवश्यकता है। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो तो सबसे पहले हंसी-खुशी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज खुश होकर हंसने में छिपा है। खासकर तनाव का सर्वाधिक अच्छा उपचार तो हास्य ही है। कई जगहों पर हास्य को एक चिकित्सा के तरीके के तौर पर देखा जाता रहा है।

अगर हमें अपने जीवन में हास्य के बारे में दूर-दूर तक अता-पता नहीं है, तो यह हमारी कमी है। इसकी तलाश हमें ही करनी होगी। यह हमारे आसपास ही कहीं होती है। सवाल है कि हास-परिहास के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसकी एक कला है और वह सीखने के लिए हमें सकारात्मक लोगों की संगत करनी होगी। दुख के क्षणों का समाधान करके सुख के दिनों की ओर बढ़ने वाले लोगों का साथ हमारे भीतर खुशी भर सकती है। तनाव को हास्य के सहारे दूर करने वाले लोग माहौल में कई बार जीवन भर देते हैं । ये अगले चरण हैं। इससे पहले हल्की- फुल्की किताबों को पढ़कर मनोरंजन करने और हास्य फिल्मों का मजा लेकर भी हम हंसने के पल चुरा सकते हैं। आजकल हर शहर में 'लाफ्टर क्लब' यानी हंसने-हंसाने वाले लोगों के जुटने की जगह होती हैं। उनका हिस्सा बनकर भी हम अपने जीवन में हंसी को शामिल कर सकते हैं। उदासी का दामन छोड़कर कुदरत की इस नियामत का सुख जीवन को एक अलग और सकारात्मक स्वरूप दे सकता है।

हालांकि इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हर जगह हम अपनी हास्य- कला का प्रदर्शन करने लगें। जहां अचानक उपजी परिस्थितियों की वजह से दुख पहाड़ सा टूट पड़ा हो, वहां दुख को हास्य के सहारे दूर नहीं किया जा सकता। ऐसी जगहों और मौकों पर हंसना शुरू कर देना या हास्य में दुख का इलाज ढूंढ़ना संवेदनहीनता का ही परिचय माना जाएगा । किसी की मृत्यु से दुखी परिवार को हम तुरंत ही यह सलाह नहीं दे सकते कि हास्य से अपने दुख को कम कर लिया जाए। हास्य निश्चित रूप से खुशहाल जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, मगर इसकी भी प्रासंगिकता होनी चाहिए। तभी इसका महत्त्व बना रह सकता है। जहां हंसने की आवश्यकता है, वहां हास्य का और जहां गंभीरता से किसी चीज का हल निकालने की जरूरत हो, वहां गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कहने का आशय यह है कि हम संतुलित जीवन जी सकते हैं, लेकिन जीवन के इस पक्ष को अपने साथ से गायब न होने दें। दुख को आने से हर बार रोका नहीं जा सकता, मगर उसका समाधान जरूर निकाला जा सकता है। जीवन प्रवहमान है। इसमें हम जिस पल दुखी होते हैं, उसी पल उस दुख के कम या दूर होने की इच्छा भी रखते हैं ।

बीतते वक्त के साथ जीवन में सहजता आती है और इस तरह हमारे चेहरे पर एक दिन हंसी सजने लगती है। इसका जीवन में बहुत अधिक महत्त्व है और इसका जीवन से गायब होना हमें निराशा की ओर ले जा सकता है। इसलिए हास्य की लगातार खोज करने की जरूरत है। हम तभी स्वस्थ और मस्त रह सकते हैं। वरना जिंदगी की आपा-धापी में बचा खुचा भी खत्म कर लेंगे। इसलिए कोशिश यही हो कि लोग खिलखिलाकर हंसने के मौके चुरा लें, कुदरत के करीब जाएं । फिर जो चमत्कार होगा, वह हमारी कल्पना से परे होगी । चेहरा चमकेगा, मित्र बनेंगे और परिवार के साथ खुशी का जीवन जी सकें, इसलिए खूब हंसे और जीवन को खुशहाल बनाएं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

पढ़ाई और सर्दियां : विजय गर्ग

सर्दियों में होने वाली परेशानियां विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधक बन सकती हैं। फ्रोजन शोल्डर, डिस्क बुल्ज और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याएं सर्दियों में अधिक प्रचलित हो जाती हैं। ठंडा मौसम और शारीरिक गतिविधियों की कमी इन समस्याओं को और गंभीर बना देती है। हालांकि, इसके समाधान मौजूद हैं। एक्टिव फिजियोथेरेपी इन समस्याओं को मैनेज करने और ठीक करने में एक प्रभावी उपाय बनकर उभरी है। आइए, इन समस्याओं को विस्तार से समझें और जानें कि एक्टिव फिजियोथेरेपी कैसे राहत प्रदान कर सकती है और कुछ छोटी- छोटी बातों का ध्यान रखकर इनसे बचा जा सकता है।

सर्दियों की समस्याएं और कारण फ्रोजन शोल्डर : फ्रोजन शोल्डर कंधे के जोड़ में जकड़न और सीमित गति के रूप में प्रकट होता है। ठंडे मौसम में रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिससे यह समस्या बढ़ जाती है। हल्की गतिविधियों की कमी और ठंड के कारण सूजन बढ़ जाती है, जिससे दर्द और परेशानी होती है।

डिस्क बुल्ज : डिस्क बुल्ज तब होता है, जब रीढ़ की हड्डियों के बीच का कुशन बाहर की ओर निकलता है और नसों पर दबाव डालता है। ठंडे मौसम में मांसपेशियां और लिगामेंट्स सख्त हो जाते हैं, जिससे दर्द बढ़ जाता है। सर्दियों में कम गतिविधि से सहायक मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे यह समस्या और जटिल हो जाती है।

ऑस्टियोआर्थराइटिस: ऑस्टियो आर्थराइटिस, जोड़ों की एक अपक्षयी समस्या, सर्दियों में अक्सर गंभीर हो जाती है। ठंडे तापमान से जोड़ सख्त हो जाते हैं, और पानी की कमी से कार्टिलेज शुष्क हो जाता है, जिससे दर्द और जकड़न बढ़ जाती है।

सिर्फ दवाएं काफी नहीं

दर्द निवारक और सूजनरोधी दवाएं अस्थायी राहत तो दे सकती हैं, लेकिन वे समस्या की जड़ को ठीक नहीं करतीं। लंबे समय तक दवाओं पर निर्भरता से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पाचन संबंधी समस्याएं या दवाओं का कम प्रभावी होना। यहीं पर एक्टिव फिजियोथेरेपी का महत्व है। यह जोड़ों की गति, मांसपेशियों की ताकत और समग्र शारीरिक कार्य को लक्षित अभ्यासों के माध्यम से सुधारने पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे मरीज अपनी समस्याओं को प्राकृतिक और स्थायी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एक्टिव फिजियोथेरेपी कैसे मदद करती है?

फ्रोजन शोल्डर के लिए एक्टिव फिजियोथेरेपी में स्ट्रेचिंग और ताकत बढ़ाने वाले अभ्यास शामिल हैं, जो कंधे के जोड़ की गतिशीलता में सुधार करते हैं। धीरे-धीरे गति की सीमा बढ़ाने वाले व्यायाम सूजन को कम करने और रक्त प्रवाह को बढ़ाने में मदद करते हैं।

कोर मजबूत करने वाले व्यायाम और रीढ़ की स्थिरता बढ़ाने वाले तकनीक डिस्क बुल्ज से पीड़ित मरीजों के लिए फायदेमंद हैं। ये अभ्यास डिस्क पर दबाव और नसों की सिकुड़न को कम करते हैं और शरीर की मुद्रा में सुधार करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस वजन उठाने वाले और लचीलापन बढ़ाने वाले अभ्यास जोड़ की जकड़न को कम करते हैं और कार्टिलेज स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। नियंत्रित गति जोड़ को चिकनाई प्रदान करने वाले तरल पदार्थ के उत्पादन को बढ़ाती है, जिससे दर्द कम होता है और गतिशीलता बढ़ती है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

दिमाग को को जकड़ता इंटरनेट मीडिया

विजय गर्ग

सूचनाओं को अक्सर ज्ञानवर्धन के जरिये के रूप में रेखांकित किया जाता है। कहा जाता है कि वे सूचनाएं ही हैं, जो नई-नई जानकारियों के रूप में हमारे अज्ञान का नाश करती हैं और जीवन को एक अर्थ प्रदान करती हैं, पर जब सूचनाओं की बमबारी हो रही हो, हमारा मस्तिष्क किसी एक स्थान पर केंद्रित न रहकर जानकारियों के जंजाल में फंसकर तय नहीं कर पा रहा हो कि किस सूचना को ग्रहण किया जाए और किसे छोड़ा जाए, तब क्या होगा ? ये सूचनाएं अर्थहीन तस्वीरों और वीडियो के रूप में हर क्षण हमारे मस्तिष्क के अधिकांश हिस्से को घेर ले रही हों, तब क्या स्थिति बनेगी ? आश्चर्य नहीं कि इंटरनेट के रास्ते हर हाथ में समाए स्मार्ट फोन पर जिस इंटरनेट मीडिया ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, उससे पैदा हो रही मानसिक अवस्था को आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ब्रेन रोट यानी दिमागी सड़न रूपी शब्द के रूप में दर्ज किया है। वर्ष 2024 के वर्ड आफ द ईयर के रूप में ब्रेन रोट का चुनाव करते हुए आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने असल में इंटरनेट मीडिया की उस बीमारी को उजागर कर दिया है, जो शायद पूरी दुनिया के लिए एक बेहद गंभीर समस्या बन गई है।

यह दिमागी जड़ता आई कहां से है? मानव सभ्यता का इतिहास देखें तो सवा दो सौ साल पहले शुरू हुए उद्योगीकरण तक इंसानों के पास ज्यादा सूचनाएं नहीं थीं, लेकिन उसका मानसिक विकास रुका नहीं। तमाम कलाएं विकसित हुई, ढेरों साहित्य रचा गया, अनेक बेमिसाल आविष्कार हुए और सभ्यता विकास के उस शीर्ष पर पहुंची, जहां पर पहुंचकर इंसान इस ज्ञात ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्रजाति बन गया, लेकिन इंटरनेट और बीते एक-डेढ़ दशक में हमारे सिर चढ़ जाने वाले इंटरनेट मीडिया ने सभ्यता के इतिहास में शायद पहली बार हमारी मानसिक या बौद्धिक स्थिति को इतने गर्त में पहुंचा दिया है, जहां छिछले ज्ञान और बेहूदा मनोरंजन को भी लोग सहजता से ग्रहण करने लगे हैं। उन्हें अर्थहीन तस्वीरों, एआइ से बनाई गईं बेहूदा सामग्रियों (कंटेंट) में कुछ भी तुच्छ नजर नहीं आता है, बल्कि ऐसी सामग्रियों को बढ़-चढ़कर देखा जाता है। ऐसी सामग्रियों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, जो असल में इंटरनेट का कचरा हैं। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि इसमें किसी का नुकसान क्या है, पर सवाल तो यह कि ऐसा कंटेंट आखिर हमारे ज्ञान, जानकारी के स्तर या फिर मनोरंजन के स्पेस में भी क्या कुछ नया और सार्थक जोड़ रहा है? व्यर्थ की तस्वीरों और वीडियो के रूप में हर दिन हजारों-लाखों छोटे कण (रील्स और शार्ट्स) हमारे दिमाग में घुस तो रहे हैं, पर ये क्षणभंगुर सामग्रियां हमें कुछ भी ऐसा विशिष्ट नहीं दे रही हैं, जो व्यक्ति, समाज या देश का कुछ भला कर सकें। डिस्पोजेबल डिजिटल कंटेंट की गंदगी कहा जा सकता है कि कुछ लोगों को इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब के शार्ट्स और इंटरनेट मीडिया के

अन्य मंचों पर ऐसा ही कंटेंट रचने से कमाई हो रही है, तो इसमें हर्ज ही क्या है। निश्चय ही, कुछ लोगों को इनसे रोजगार मिला है, लेकिन ऐसे लोगों की इंटरनेट मीडिया पर परोसी गंदगी जब हम तक पहुंचती है तो वह धीरे-धीरे हमारे दिमाग को सुन्न करने लगती है। फेंके जाने योग्य डिजिटल सामग्री (डिस्पोजेबल डिजिटल कंटेंट) रूपी यह गंदगी असल में हमारे मस्तिष्क के एक मूल्यवान स्थान को स्थान घेर लेती है। ज्यादातर स्थितियों में एक नकारात्मक प्रवृत्ति की तरह जकड़े और सड़ते हुए दिमाग को और अधिक गंदगी की चाहत होती है। यही कारण है कि जब आप कुछ समय के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कोई रील देखते हैं, तो एक के बाद एक करते हुए घंटों तक उन्हें ही देखते रहते हैं। यह असल में दिमाग को सुन्न करने वाली एक ऐसी प्रवृत्ति है, जिसमें एक स्थिति आने पर व्यक्ति को लगने लगता है कि वह किसी की जकड़ में है, पर उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नहीं सूझता है। हालांकि दिमागी सड़न के कुछ प्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य देखे जा सकते हैं। जैसे, इससे किसी वस्तु - विषय पर ध्यान केंद्रित (फोकस) करने की अवधि घट जाती है। इसका असर यह होता है कि हमारे मस्तिष्क का सकारात्मक गतिविधियों में संलग्न होना मुश्किल हो जाता है । जैसे, हम किताबें नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ ऐसा रच नहीं पाते हैं, जो हमें भीतरी संतुष्टि प्रदान करता है। चिंतन करने, शोध करने और सोच-विचार कर आविष्कार करने की सहज प्रवृत्ति कमजोर होने लगती है। इंटरनेट मीडिया के उद्भव के साथ दिमागी जकड़न के शिकार ऐसे लोगों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, जो फूहड़ता की श्रेणी में आने वाली ऐसी सामग्रियों के दर्शक, प्रशंसक हैं, जो असल में अर्थहीन डिजिटल मलबे से ज्यादा कुछ नहीं हैं। समस्या यह है कि सूचनाएं और मनोरंजन प्रदान करने वाली कंपनियां भी बाजार मांग को देखते हुए ऐसी फूहड़ सामग्रियों का उत्पादन करने लगी हैं। ये अपने दर्शकों को ज्ञान, सूचना या वास्तविक मनोरंजन जैसा कुछ भी नहीं देती हैं। अगर हमारा मस्तिष्क एक स्थाई किस्म की जड़ता का शिकार हो रहा है तो कह सकते हैं कि हमारी असली जिंदगी पर वह नकली वर्चुअल जिंदगी हावी हो गई। है, जिसका वास्तविक दुनिया और उसकी जटिलताओं से कोई सरोकार नहीं है। डिजिटल उपवास में समाधानः बीते एक दशक में ऐसे कई शोध हुए हैं, जो बताते हैं कि इंटरनेट मीडिया एक बुरी लत में बदल रहा है। इससे मुक्ति का एक नया ट्रेंड 'इंटरनेट उपवास' है, जिसे कुछ विशेषज्ञ डोपामाइन फास्टिंग का नाम भी देते हैं। इसकी जरूरत उन लोगों को है, जो असल में इंटरनेट मीडिया, आनलाइन गेमिंग और पोर्नोग्राफी की लत के शिकार हो चुके हैं। यानी उनका दिमाग

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में अपार संभावनाएं, क्या सरकार से मिलेगी जरूरी मदद?

परिवहन विशेष न्यूज

उत्तराखंड में ऑटोमोबाइल सेक्टर के बाद इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक दूसरा सबसे अधिक फलने-फूलने वाला सेक्टर है। इस क्षेत्र में अभी भी अपार संभावनाएं है और इसे केंद्र से सतत सहयोग की दरकार है। इस क्षेत्र से जुड़े उद्यमी भी चाहते हैं कि विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार रियायतें देने के साथ ही बजटीय प्रावधान भी करे।

देहरादून। पर्यावरणीय दृष्ट से संवेदनशील उत्तराखंड में औद्योगिक विकास किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र का विषम भूगोल और पर्यावरणीय परिस्थितियां औद्योगिक विकास की राह में दुश्वारियां खड़ी करते आए हैं। इस सबको देखते हुए राज्य में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर विशेष जोर दिया जाता आ रहा है, जो यहां की पर्यावरणीय परिस्थितियों के एकदम अनुकूल है।

यही कारण है कि यह प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर के बाद दूसरा सबसे अधिक फलने-फूलने वाला सेक्टर है। इस क्षेत्र में अभी भी अपार संभावनाएं है और इसे केंद्र से सतत सहयोग की दरकार है। इस क्षेत्र से जुड़े उद्यमी भी चाहते हैं कि विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार रियायतें देने के साथ ही बजटीय प्रविधान भी करे।

उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की तस्वीर देखें तो यह अभी तक मुख्य रूप से रुड़की, रुद्रपुर, सितारगंज, देहरादून, हरिद्वार व कोटद्वार इसके बड़े केंद्र हैं। यहां इलेक्ट्रिक बल्ब से लेकर कंप्यूटर व ड्रोन तक बनाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक का सालाना कारोबार तकरीबन 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है। इसमें तकरीबन तीन लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है।

यद्यपि, राज्य से होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात में मशीनरी व यांत्रिक उपकरणों की भागीदारी 9.07 प्रतिशत है, जिसे सरकारी प्रोत्साहन मिलने पर बढ़ाया जा सकता है। राज्य में स्थापित इलेक्ट्रानिक उद्योग अपनी-अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन चुनौतियों की भी भरमार है।

जिन औद्योगिक क्षेत्रों में यह इकाइयां हैं, वहां सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। साथ ही लाजिस्टिक और परिवहन नेटवर्क कमजोर होने के कारण उत्पादन व आपूर्ति की श्रृंखला प्रभावित हो रही है। उद्योगों को कुशल कार्यबल की उपलब्धता भी कम बड़ी चुनौती नहीं है। कच्चे माल की उपलब्धता न होने के कारण इसके लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।

काशीपुर में बन रहा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर

काशीपुर में राज्य का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से संचालित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना के तहत इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान किया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ ही आर्थिक वृद्धि हो सकेगी।

क्या चाहते हैं उद्यमी?

प्रदेश में एक मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो।

इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में कुशल कार्यबल की हो उपलब्धता।

प्रौद्योगिकी व नवचार के लिए अनुसंधान में किया जाए निवेश।

राज्य और केंद्र की नीतियों में स्पष्टता और स्थिरता जरूरी।

कच्चे माल की अनुपलब्धता की दिशा में हो काम।

पर्यावरण से जुड़े मानकों में ढील दी जाए।

क्या कहते हैं उद्यमी?

लघु भारती के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह तोमर का कहना है कि इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में गुणात्मक सुधार की जरूरत है। इस क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत अधिक बजट स्वीकृत किया जाना चाहिए।' वहीं, पीएचडी चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, उत्तराखंड के को-चेयरमैन राजीव घई की अपील है कि केंद्र सरकार को उत्तराखंड की विशेष परिस्थिति को देखते हुए उद्योग क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज और जीएसटी में छूट देनी चाहिए।

अब उपभोक्ताओं को ठगना होगा मुश्किल, सरकार ने तैयार किया मास्टरप्लान

उपभोक्ताओं को समय पर न्याय दिलाने और आम लोगों को शिकायत के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले का मंत्रालय 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के अवसर पर ई-जागृति ऐप शुरू कर सकता है। पिछले साल 24 दिसंबर को ई-जागृति पोर्टल शुरू किया गया था लेकिन अभी यह पोर्टल पूरी तरह से संचालन में नहीं आ पाया है।

नई दिल्ली। उपभोक्ताओं के साथ धोखा अब आसान नहीं होगा। अभी साधारण उपभोक्ता अमूमन किसी दुकानदार, कंपनी या सेवा मुहैया कराने वालों की तरफ से ठगे जाने के बावजूद भी उनकी शिकायत उपभोक्ता फोरम पर करने से परहेज करते हैं। क्योंकि इसकी प्रक्रिया की जानकारी उन्हें नहीं होती है और इस काम में उन्हें लिखित रूप से चीजें देनी पड़ती है।

हालांकि, जागरूक उपभोक्ताओं की तरफ से अब भी साल भर में लाखों की संख्या में इंश्योरेंस सेक्टर, ई-कॉमर्स कंपनियां व अन्य कंपनियों के उत्पादों के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायतें की जाती है, लेकिन सुनवाई में देर होने व मामले का लगातार अनुसरण करने के झंझट से जागरूक उपभोक्ताओं को भी कई बार न्याय नहीं मिल पाता है।

उपभोक्ताओं को समय पर न्याय दिलाने और आम लोगों को शिकायत के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले का मंत्रालय 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के अवसर पर ई-जागृति ऐप शुरू कर सकता है। पिछले साल 24 दिसंबर को ई-जागृति पोर्टल शुरू किया गया था, लेकिन अभी यह पोर्टल पूरी तरह से संचालन में नहीं आ पाया है। आगामी 24 दिसंबर से इस पोर्टल को पूरी तरह संचालन में लाने की भी शुरुआत हो सकती है।

ई-जागृति पोर्टल के संचालन में आने पर उपभोक्ताओं को शिकायत के लिए राज्य व जिला उपभोक्ता अदालत के फोरम के पास नहीं जाना होगा। वे अपने मोबाइल फोन या - ईमेल आईडी से लागइन करके पूरी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। फीस से लेकर अन्य संबंधित दस्तावेज भी अपलोड हो जाएंगे और पोर्टल व ऐप पर ही उन्हें सुनवाई की जानकारी मिल जाएगी। वर्चुअल सुनवाई की सुविधा होगी और शारीरिक उपस्थिति की कोई जरूरत नहीं होने पर उपभोक्ता कहीं भी रहकर अपने मामले को लगातार देख सकेगा।

अभी देश भर में सालाना पांच लाख से अधिक उपभोक्ता अदालत व संबंधित फोरम में शिकायतें दर्ज होती हैं। इनमें से कई मामले विभिन्न कारणों से महीनों लंबित रहते हैं। ई-जागृति पोर्टल के काम करना शुरू कर देने पर मामलों का निपटान आसान हो जाएगा और इससे उपभोक्ता अपने अधिकार के प्रति सजग होंगे।

उपभोक्ता दिवस पर जमैटो, आजियो, बिग बास्केट जैसी कई ऑनलाइन कंपनियां उपभोक्ताओं को सुरक्षा की भी शपथ ले सकते हैं। कंपनियां इस बात की शपथ लेंगी कि वे अपने प्लेटफार्म पर कोई भी असुरक्षित और उपभोक्ताओं के लिए खतरनाक वस्तुओं की बिक्री नहीं करेंगे।

मोबिक्विक, विशाल मेगा मार्ट का IPO Allotment Status कैसे चेक करें; जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

आईपीओ ओवरसब्सक्राइब होने पर अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम से होता है। लॉटरी सिस्टम की पूरी प्रक्रिया रजिस्ट्रार की निगरानी में होती है। अगर आपने भी मोबिक्विक विशाल मेगा मार्ट और लाइफ साइंसेज के आईपीओ के लिए आवेदन किया है तो आप बीएसई या रजिस्ट्रार की वेबसाइट से अलॉटमेंट स्टेटस जांच सकते हैं। आइए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं।

नई दिल्ली। इस हफ्ते मोबिक्विक, विशाल मेगा मार्ट और साई लाइफ साइंसेज के आईपीओ की शेयर मार्केट में एंट्री होने वाली है। ये तीनों ही आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक खुले थे। इन तीनों आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आज यानी 16 दिसंबर (सोमवार) को आएगा। आइए जानते हैं कि आप इनका अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं।

ग्रे मार्केट में मोबिक्विक, विशाल मेगा मार्ट और साई लाइफ साइंसेज के आईपीओ को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मोबिक्विक का लेटेस्ट जीएमपी (Mobikwik IPO GMP) 59.14 फीसदी है। विशाल मेगा मार्ट आईपीओ का जीएमपी (Vishal Mega Mart IPO GMP) फिलहाल 24.36 फीसदी है। साई लाइफ साइंसेज (Sai Life Sciences IPO GMP) का 11.11 फीसदी पर पहुंच गया है।

IPO अलॉटमेंट कैसे होता है?

अगर कोई आईपीओ ओवर-सब्सक्राइब होता है, तो अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम से होता है। जैसा कि मोबिक्विक, विशाल मेगा मार्ट और साई लाइफ साइंसेज के मामले में हुआ है। बहुत-से अच्छे और बड़े आईपीओ ओवर-सब्क्राइब होते हैं, तो यह प्रोसेस अमल में लाया जाता है। लॉटरी सिस्टम की पूरी प्रक्रिया रजिस्ट्रार की निगरानी में होती है। आप मोबिक्विक, विशाल मेगा मार्ट और लाइफ साइंसेज के आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस बीएसई या रजिस्ट्रार की वेबसाइट से जांच सकते हैं।

IPO Allotment Status पता करने का प्रोसेस

आईपीओ अलॉटमेंट पता करने के दो रास्ते हैं। आप बीएसआई की आधारिक साइट या फिर रजिस्ट्रार की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं।

निवेश के लिए रहें तैयार, 19 दिसंबर को खुलेंगे चार कंपनियों के आईपीओ

परिवहन विशेष न्यूज

19 दिसंबर को चार कंपनियों के आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। इनमें डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड और सनाथन टेक्सटाइल्स शामिल हैं। इन सभी आईपीओ में शेयर खरीदने के लिए 23 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने भी आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज जमा कर दिए हैं।

नई दिल्ली। अगर आप आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में निवेश करते हैं तो तैयार रहिये। इस सप्ताह 19 दिसंबर को चार कंपनियों के आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। इस सप्ताह जो कंपनियां आईपीओ ला रही हैं, उनमें डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स, कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम, ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड और सनाथन टेक्सटाइल्स शामिल हैं। इन सभी आईपीओ में शेयर खरीदने के लिए 23 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है।

डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स का 840.25 करोड़ रुपये का आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फार सेल (ओएफएस) पर आधारित है। इस आइपीओ में प्रमोटरों के 2.97 करोड़ इक्विटी शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। आईपीओ का प्राइस बैंड 269-283 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

कॉनकार्ड एनवायरो सिस्टम आईपीओ के जरिये 500.33 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। आईपीओ में 175 करोड़ रुपये के नए शेयर और 325.33 करोड़ रुपये के प्रमोटर शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 665-701 रुपये प्रति शेयर तय किया है।

इसी तरह, ट्रांसरेल लाइटिंग ने 839 रुपये के आईपीओ का प्राइस बैंड 410-432 रुपये प्रति शेयर तय किया है। आईपीओ में 400 करोड़ रुपये के नए शेयर और प्रमोटरों के 1.01 करोड़ शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। सनाथन टैक्सटाइल ने अपने 550 करोड़ रुपये के आइपीओ का प्राइस बैंड 305-321 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इस आइपीओ में 400 करोड़ रुपये के नए शेयर और 150 करोड़ रुपये के प्रमोटर शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे।

आनंद राठी स्टाक ब्रोकर्स ने जमा किए दस्तावेज

आनंद राठी समूह की ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने आईपीओ के जरिये 745 करोड़ रुपये जुटाने के लिए सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज जमा कर दिए हैं। दस्तावेजों के अनुसार, यह पूरा आईपीओ नए शेयरों पर आधारित होगा। यानी इस आइपीओ में प्रमोटर शेयकों की बिक्री नहीं की जाएगी।

सोलर पावर से चलने वाले कृषि वाटर पंप सिस्टम बनाने वाली कंपनी जीके एनर्जी लिमिटेड ने भी 500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए सेबी के पास आईपीओ दस्तावेज जमा किए हैं। दस्तावेजों के अनुसार, इस आइपीओ में नए और प्रमोटर शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। नए शेयरों की बिक्री से जुटाए जाने वाले 422.46 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कंपनी अपनी लंबी अवधि की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में करेगी।

ईपीएफ के पैसों से होम लोन चुकाना सही या गलत?

परिवहन विशेष न्यूज

आईपीओ ओवरसब्सक्राइब होने पर अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम से होता है। लॉटरी सिस्टम की पूरी प्रक्रिया रजिस्ट्रार की निगरानी में होती है। अगर आपने भी मोबिक्विक विशाल मेगा मार्ट और लाइफ साइंसेज के आईपीओ के लिए आवेदन किया है तो आप बीएसई या रजिस्ट्रार की वेबसाइट से अलॉटमेंट स्टेटस जांच सकते हैं। आइए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं।

नई दिल्ली। इस हफ्ते मोबिक्विक, विशाल मेगा मार्ट और साई लाइफ साइंसेज के आईपीओ की शेयर मार्केट में एंट्री होने वाली है। ये तीनों ही आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक खुले थे। इन तीनों आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आज यानी 16 दिसंबर (सोमवार) को आएगा। आइए जानते हैं कि आप इनका अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं।

ग्रे मार्केट में मोबिक्विक, विशाल मेगा मार्ट और साई लाइफ साइंसेज के आईपीओ को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मोबिक्विक का लेटेस्ट जीएमपी (Mobikwik IPO GMP) 59.14 फीसदी है। विशाल मेगा मार्ट आईपीओ का जीएमपी (Vishal Mega Mart IPO GMP) फिलहाल 24.36 फीसदी है। साई लाइफ साइंसेज (Sai Life Sciences IPO GMP) का 11.11 फीसदी पर पहुंच गया है।

IPO अलॉटमेंट कैसे होता है?

अगर कोई आईपीओ ओवर-सब्सक्राइब होता है, तो अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम से होता है। जैसा कि मोबिक्विक, विशाल मेगा मार्ट और साई लाइफ साइंसेज के मामले में हुआ है। बहुत-से अच्छे और बड़े आईपीओ ओवर-सब्क्राइब होते हैं, तो यह प्रोसेस अमल में लाया जाता है। लॉटरी सिस्टम की पूरी प्रक्रिया रजिस्ट्रार की निगरानी में होती है। आप मोबिक्विक, विशाल मेगा मार्ट और लाइफ साइंसेज के आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस बीएसई या रजिस्ट्रार की वेबसाइट से जांच सकते हैं।

IPO Allotment Status पता करने का प्रोसेस

आईपीओ अलॉटमेंट पता करने के दो रास्ते हैं। आप बीएसआई की आधारिक साइट या फिर रजिस्ट्रार की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं।

बीएसई साइट पर अलॉटमेंट चेक करने का तरीका

बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) की आधिकारिक साइट पर जाएं।

इश्यू टाइप में इक्विटी और डेट ऑप्शन में से इक्विटी सेलेक्ट करें।

ड्रॉपडाउन में आईपीओ चुनें, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है।

अलॉटमेंट स्टेटस जांचने के लिए आवेदन संख्या या PAN दर्ज करें।

रजिस्ट्रार साइट की साइट पर अलॉटमेंट कैसे चेक करें?

थोक महंगाई में भी मिली राहत, तीन महीने के निचले स्तर पर आई

परिवहन विशेष न्यूज

नवंबर में खाने-पीने की चीजें के दाम घटे हैं। यह अक्टूबर में 13 .54 फीसदी थी जो नंवबर में 8 .63 फीसदी पर आ गई। सब्जियों की महंगाई दर 63 .04 फीसदी से गिरकर 28 .57 फीसदी पर आ गई। हालांकि आलू का भाव नीचे नहीं आया। इसकी महंगाई दर उछलकर 82.79 फीसदी पर पहुंच गई। प्याज के मामले में राहत मिली और इसका इन्फ्लेशन गिरकर 2.85 फीसदी पर आ गया।

नई दिल्ली। खुदरा महंगाई के बाद नवंबर में थोक भाव पर आधारित महंगाई (WPI Inflation) से भी राहत मिली है। यह तीन महीने के निचले स्तर पर आ गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बयान के मुताबिक, होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) पर आधारित मुद्रास्फीति नवंबर में 1.89 फीसदी पर आ गई।

यह अक्टूबर में 2.36 फीसदी पर थी। वहीं, पिछले साल नवंबर में यह 0.39 फीसदी पर थी। खुदरा महंगाई दर के आंकड़े 12 दिसंबर को आए थे। नवंबर में खुदरा महंगाई की दर घटकर 5.48 फीसदी रही, जो अक्टूबर में 6.21 फीसदी रही थी।

किन चीजों के सस्ता होने से घटी थोक महंगाई?

नवंबर में खाने-पीने की चीजें के दाम घटे हैं। यह अक्टूबर में 13.54 फीसदी थी, जो नंवबर में 8.63 फीसदी पर आ गई। सब्जियों की महंगाई दर 63.04 फीसदी से गिरकर 28.57 फीसदी पर आ गई। हालांकि, आलू का भाव नीचे नहीं आया। इसकी महंगाई दर उछलकर 82.79 फीसदी पर पहुंच गई। प्याज के मामले में राहत मिली और इसका इन्फ्लेशन गिरकर 2.85 फीसदी पर आ गया।

नवंबर में खुदरा महंगाई में भी मिली थी राहत

खुदरा महंगाई का डेटा पिछले महीने (12 दिसंबर) को आया था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) पर आधारित रिटेल इन्फ्लेशन अक्टूबर में 6.21 फीसदी से घटकर नवंबर में 5.48 फीसदी पर आ गया। इसमें भी गिरावट खाने-पीने का सामान सस्ता होने की वजह से आई थी। नवंबर में फूड इन्फ्लेशन घटकर 10.9 फीसदी से 9 फीसदी पर आ गई थी।

हालांकि, आरबीआई और सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि रिटेल इन्फ्लेशन लगातार तीसरे महीने 5 महीने से ऊपर बनी रही। सरकार ने आरबीआई को महंगाई दर को 2 से 4 फीसदी के दायरे में रखने का टारगेट दिया है।

क्यों घट रही है खाद्य महंगाई

थोक और खुदरा महंगाई दर कम होने की सबसे बड़ी वजह खाने-पीने की चीजों का दाम घटना है। दरअसल, मानसूनी बारिश के चलते नवंबर से पहले के महीने में सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन पर बुरा असर पड़ा था। साथ ही, बाढ़ के चलते फसलें खराब होने के मामले में भी आए थे। नवंबर में बेहतर खरीफ फसलों के उत्पादन और बाजार में साग-सब्जियों की आवक के बढ़ने के चलते महंगाई में कमी आ रही है। यह सिलसिला आने वाले महीनों में भी जारी रहने की उम्मीद है।

बद्दी की फार्मा इंडस्ट्री की गुहार, यूरोप से टक्कर के लिए मदद दे सरकार

हिमाचल प्रदेश के बद्दी में इस समय 675 उद्योग स्थापित हैं। नामी फार्मा उद्योगों में अबाट हेल्थकेयर सिप्ला फार्मा ग्लेनमार्क रैनबैक्सी डॉ. रेड्डी सन फार्मा पिनाकल लाइफ साइंस पार्क फार्मास्युटिकल टार्क स्कॉट एडिल एमिली टारेंट एलकेम लैब सहित अनेक फार्मा उद्योग स्थापित हैं। प्रदेश में निर्मित 35 प्रतिशत दवाओं का निर्यात किया जाता है जो 150 से अधिक देशों में भेजी जाती हैं।

सोलन। हिमाचल से प्रतिवर्ष 40 हजार करोड़ रुपये की दवा का कारोबार होता है। देश के कुल दवा कारोबार में बद्दी सहित हिमाचल की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत है। केंद्र सरकार का सहयोग रहा तो भारत में 2028 तक यूरोपीय देशों के मानकों के अनुरूप दवा का उत्पादन होगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दुनियाभर में दवा उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल एम को लागू किया है, जिसे अपनाने में भारत का फार्मा सेक्टर जुटा है। अगर सरकार की तरफ से कोलैटरल फ्री लोन (कुछ भी गिरवी रखे बिना) उपलब्ध कराया जाता है तो फार्मा सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी।

भारत हर वर्ष तीन लाख करोड़ रुपये की दवा का उत्पादन करता है। करीब 10 हजार फार्मा उद्योग दुनियाभर में दवा निर्यात करते हैं। भारत में डेढ़ लाख प्रत्यक्ष और करीब तीन लाख लोग परोक्ष रूप से फार्मा उद्योग से जुड़े हैं।

अभी यूरोपियन देशों के स्तर की दवा उत्पादन तैयार करने में कुछ समय लगेगा। ऐसा करने में केंद्र सरकार मदद करेगी तो वर्ष 2028 तक यह संभव हो सकेगा। इस समय भारत का फार्मा उद्योग रिवाइज्ड शेडयूल एम के मुताबिक अपने उद्योगों को तैयार कर रहा है। केंद्र सरकार उद्यमियों को कोलैटरल-फ्री लोन उपलब्ध कराती है तो उससे फार्मा सेक्टर को बड़ी राहत महसूस होगी।

सतीश सिंघल, प्रबंधक यूनिसीड्स फार्मा एवं पूर्व चेयरमैन हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन

हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के महासचिव मनीष ठाकुर का कहना है कि फार्मा की पढ़ाई करने वाले युवा पूरी तरह शिक्षित नहीं हैं। उन्हें नए मानकों के मुताबिक कुशल बनाना होगा। फार्मा में काम करने वाले बच्चों की शुरू से पढ़ाई अच्छी होगी तो दवा भी बेहतर बनकर तैयार होगी। फार्मा के कर्मियों को जागरूक करने के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाने होंगे, जिससे दवा उत्पादन व गुणवत्ता में काफी प्रभावशाली असर होगा।

पहाड़ी राज्यों के उद्यमियों को केंद्र सरकार को सहयोग के तौर पर सब्सिडी या पैकेज देना चाहिए। अब तक हिमाचल के फार्मा उद्योग बद्दी तक रेल नहीं पहुंच सकी है। केंद्र सरकार को जल्द बजट उपलब्ध करवाकर इसे पूरा करवाना चाहिए। इससे दवा उद्यमियों को राहत मिलेगी और महंगे परिवहन से छुटकारा मिलेगा।

संजय शर्मा, कोषाध्यक्ष, हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन

बद्दी में स्थापित हैं 675 उद्योग

हिमाचल प्रदेश के बद्दी में इस समय 675 उद्योग स्थापित हैं। नामी फार्मा उद्योगों में अबाट हेल्थकेयर, सिप्ला फार्मा, ग्लेनमार्क, रैनबैक्सी, डॉ. रेड्डी, सन फार्मा, पिनाकल लाइफ साइंस, पार्क फार्मास्युटिकल, टार्क, स्कॉट एडिल, एमिली, टारेंट, एलकेम लैब सहित अनेक फार्मा उद्योग स्थापित हैं। प्रदेश में निर्मित 35 प्रतिशत दवाओं का निर्यात किया जाता है, जो 150 से अधिक देशों में भेजी जाती हैं। 65 प्रतिशत दवाओं को भारत के अलग-अलग राज्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है।

फार्मा उद्यमियों की प्रमुख मांगें

फार्मा उद्यमी रिवाइज्ड शेड्यूल एम व अन्य अपग्रेडेशन के लिए कोलैटरल-फ्री लोन की मांग कर रहे हैं।

जीएसटी लागू होने के बाद सभी राज्यों में एक जैसा टैक्स सिस्टम है। ऐसे में पहाड़ी राज्यों को विशेष पैकेज की उम्मीद है।

फार्मा उद्योगों तक रेल विस्तार का कार्य जल्द से जल्द पूरा हो।

हिमाचल में महंगा परिवहन है, केंद्र को इनकम टैक्स में सब्सिडी देनी चाहिए।

क्या है रिवाइज्ड शेड्यूल एम

रिवाइज्ड शेड्यूल एम औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 का एक हिस्सा है। इसमें फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए अच्छे विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) और परिसर, संयंत्र, और उपकरणों से जुड़ी जरूरतों को बताया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छह जनवरी को संशोधित नियम अधिसूचित किए थे। इन नियमों का उद्देश्य, फार्मा और बायोफार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना है।

जेएसएससी भर्ती परीक्षा रद्द कराने को लेकर रांची मे लाठीचार्ज

भाजपा ने आन्दोलन कारियों का पक्ष लिया

कार्तिक परिच्छा,स्टेट हेड- झारखंड

रांची। रांची में अभ्यर्थियों ने सोमवार को एसएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे कि प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी. मामला सितंबर की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितता का था, जिस मामले को लेकर झारखंड का गत विधानसभा सत्र भी गर्म हुआ था । अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की. आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की थी. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती रही. सभी गेट पर अवरोधक भी लगाए गए थे.

प्रदर्शन की अगुवाई झारखंड राज्य छात्र संघ के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने की. उन्होंने कहा कि भारी सुरक्षा इंतजाम और निषेधाज्ञा के बावजूद छात्र जेएसएससी कार्यालय के पास इकट्ठा हुए. उन्होंने कहा कि आंदोलन का मकसद भर्ती परीक्षा को रुकवाना है. बता दें कि जेएसएससी की तरफ से दस्तावेज सत्यापन का काम शुरू हो गया है. 16 से 22 दिसंबर के बीच चयनित 2,231 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है. उन्होंने झारखंड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (जेजीजीएलसीसीई) उत्तीर्ण की है. परीक्षा में 3.04 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे. छात्रों के प्रदर्शन की वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने दावा किया कि एसएससी कार्यालय का घेराव करने 24 जिलों से हजारों अभ्यर्थी पहुंचे हैं.

इससे पहले प्रशासन ने शनिवार सुबह 5.30 बजे से 20 दिसंबर रात 8 बजे तक एसएससी कार्यालय के 500 मीटर के दायरे में बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. रविवार को आधिकारिक बयान में कहा गया था कि प्रशासन आंदोलन से निपटने के लिए तैयार है.

कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए आंदोलनकारी छात्रों को आक्रामक प्रदर्शन से दूर रहने की हिदायत दी गयी थी. जेजीजीएलसीसी परीक्षा सरकार में ज्यादातर जूनियर स्तर के पदों पर भर्ती का माध्यम है.

अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है. 30 सितंबर को भी जेएसएससी कार्यालय के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन कर परीक्षा रद्द करने की मांग की थी. जेएसएससी ने अभ्यर्थियों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए अनियमितताओं की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था. आरोपों को खारिज करते हुए जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता ने कहा कि परीक्षा स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की गई थी. समाचार लिखे जाने तक भारतीय जनता पार्टी इस लाठीचार्ज के खिलाफ आवाज बुलंद किया है । भाजपा के कई विधायक सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं ।

खेल प्रतियोगिताओं के समापन समारोह पर पहुंचे पूर्व केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर..

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में विवेक बिधूड़ी फाउंडेशन द्वारा व एल.पी.जी., ई.आई.एल और फेना प्रा0लिमि0 के सहयोग से 11 दिसम्बर से शुरू हुए क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल और खो-खो टूर्नामेन्ट लीग मैचों के 15 दिसम्बर को फाइनल मुकाबले महरौली-बदरपुर रोड़ स्थित डीडीए स्पोर्टस ग्राउंड तुगलकाबाद में खेले गए। इस दौरान प्रतियोगिताओं के समापन अवसर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अम्पायर अनिल चैधरी खेल प्रतियोगिता में अम्पायर के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी व तुगलकाबाद गॉव के सम्मानित बुजुर्गों ने उनका अभिनन्दन किया।

इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जो कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता वह देश का युवा खिलाड़ी कर सकता है, देश के खिलाड़ी में वो ताकत है जो किसी भी देश की खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर स्वर्ण पदक जीतेगा तो भारत के सम्मान में राष्ट्रगान की धुन के साथ तिरंगा झण्डा भी उस देश में फेहराया जाएगा जो सिर्फ एक खिलाड़ी की ताकत ही कर सकती है। उन्होंने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी का खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से खेल को आगे बढ़ाने की दिशा में इस प्रयास के लिए धन्यवाद किया।

रमेश बिधूड़ी ने अपने सम्बोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हर वर्ग को छूने का प्रयास किया है, खेल का क्षेत्र ऐसा है जहॉ से स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, चरित्र निर्माण और सबसे ऊपर एक सौहार्द, ना जाति, ना धर्म, ना क्षेत्रवाद केवल एकता और राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है। उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए पिछले 4 वर्षों से दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में निरंतर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं में छिपी प्रतिभाएं निखर रही हैं। उन्होंने आगे बताया कि माननीय मोदी जी के खेलो इंडिया राष्ट्रीय कार्यक्रम उन गरीब कमजोर वर्ग व ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का मंच प्रदान कर रहा है जो युवा खेलों में रूचि रखते हैं परन्तु आर्थिक कारणों से खेलों में अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित नहीं कर पाते ऐसे नौजवानों को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए मा0 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेल मंत्री रहे अनुराग ठाकुर जी ने खेल बजट को बढ़ाकर 2000 करोड़ करने का काम किया जो बजट पहले कभी 300-400 करोड़ का हुआ करता था। आज मोदी जी के नेतृत्व में खेल को एक नया दृष्टिकोण व भारत को विश्व स्तर पर एक नई पहचान मिली है।

अंगनावाड़ी कार्यकर्ताओं की धरना उपमुख्यमंत्री ने कहा आलोचना करो

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : लोअर पीएमजी में अंगनावाड़ी की पत्रकारिता। सरकारी अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की मांग करने के लिए हजारों अंगनावाड़ी कार्यकर्ता और सहायक एक साथ आए हैं। यह आंदोलन बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली और सरकार के चुनाव पूर्व वादों को लागू करने की मांग को लेकर उतरा है।उपमुख्यमंत्री पंधी परिदा ने भुवनेश्वर लोअर पीएमजी में अंगनावाड़ी कार्यकर्ताओं के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उपमुख्यमंत्री ने कहा, नई सरकार आए अभी 6 महीने ही हुए हैं। पहले सरकार से बात करें, चर्चा के बाद आंदोलन के लिए राजमार्ग पर आएं, उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिदा ने कहा।

मणिपुर में प्रवासी मजदूरों की हत्या मामले में सात उग्रवादी हिरासत में, सीएम ने बताया आतंकवादी कृत्य

परिवहन विशेष न्यूज

मणिपुर में बिहार के दो प्रवासी मजदूरों की हत्या मामले में सात उग्रवादियों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस घटना को आतंकवादी कृत्य करार दिया है और मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। घटना पर बिहार सीएम नीतीश कुमार ने भी शोक जताया है।

इंफाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दो प्रवासी मजदूरों की हत्या मामले में बयान दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि बिहार के दो प्रवासी मजदूरों की हुई हत्या के मामले में एक उग्रवादी संगठन के संदिग्ध सात सदस्यों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

इसके अलावा सीएम ने दोनों प्रवासी मजदूरों के परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मामला एनआईए को भी सौंपा जा सकता है।

सीएम ने बताया राजनीतिक रूप से प्रेरित समूहों का हाथ

पुलिस ने बताया कि मणिपुर के काकचिंग जिले में शनिवार शाम को बिहार के दो मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीएम एन बीरेन सिंह ने विजय दिवस समारोह के दौरान कहा कि हमें हत्याओं के पीछे राजनीतिक रूप से प्रेरित समूहों का हाथ होने का संदेह है। निश्चित रूप से हम अपराधी का पता लगा लेंगे। सीएम एन बीरेन सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैं मणिपुर के काकचिंग जिले में बिहार के युवा भाइयों, सुनालाल कुमार और दशरथ कुमार की हत्या किए जाने की कड़ी निंदा करता हूं। आतंकवाद का यह कृत्य हमारे मूल्यों पर सीधा हमला है। मेरी गहरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवारों के साथ हैं।

नीतीश कुमार ने भी जताया शोक

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हत्याओं पर शोक व्यक्त किया और मृतकों के स्वजनों को दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की। वहीं, पुलिस के एक बयान में सोमवार को कहा गया कि सुरक्षा बलों ने मणिपुर के कांगपोकपी जिले में तलाशी अभियान के दौरान हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा जब्त किया है। वहीं, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आरोप लगाया कि ₹कुछ एजेंसियां₹ राज्य के बारे में गलत जानकारी नई दिल्ली को भेज रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र को इस मामले की जानकारी है और वह जमीनी स्तर से जानकारी एकत्र कर रहा है। कहा- केंद्र को एहसास हो गया है राजधानी इंफाल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, 'कुछ एजेंसियों द्वारा नई दिल्ली को गलत सूचना, जोड़-तोड़ वाली और राजनीतिक जानकारी भेजी गई थी।

न्यायालय ने दोनों पक्षो को सुनने के उपरांत मुलज़ीमानों को किया दोषमुक्त

अभियुक्त की तरफ से पैरवी विद्वान अधिवक्ता अरविन्द पुष्कर द्वारा की गयी एडवोकेट अरविन्द द्वारा मजबूती से रखें गए तर्कों को सुनने के उपरांत अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में रहा असफल

आगरा, संजय साग़र सिंह। जिला एवं सत्र न्यायालय दीवानी कचहरी में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, न्यायालय संस्था 11 के विशेष सत्र परीक्षण संख्या-40/2014 में आरोपित के अधिवक्ता द्वारा मजबूती एवं गंभीरता के साथ रखें गए तर्कों को सुनने के उपरांत अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा तथा न्यायालय ने दोनों पक्षो को सुनने के उपरांत न्यायहित में अपने एक आदेश में अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने योग्य मानते हुए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए आरोपमुक्त कर दिया।

इस बावत आरोपित के विद्वान अधिवक्ता अरविन्द कुमार पुष्कर ने न्यायालय के आदेशानुसार बताया कि वर्ष 2014 से विचाराधीन सत्र परिक्षण संरखा 40/14 में अभियुक्त विपिन पुत्र राजकुमार निवासी जिला मैनपुरी को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, द्वारा दोनों पक्षों को गंभीरता से सुनने के उपरांत मुलज़ीमानों को दोषमुक्त किया गया।

उन्होंने आगे कहा, ₹संक्षेप में अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि वादी अनिल कुमार यादव की तहरीर 17/12/13 को उनकी माताजी द्वारा मुलज़ीमान के विरुद्ध मुक़दमा दायर कराया गया था कि वो स्टेट बैंक में से 10 हजार रुपये निकाल कर ला रही थी, तभी दो अज्ञात लड़कों ने उनसे रुपयों का बैग छीन लिया और रुपये लेकर भाग गए।

अंत में श्री पुष्कर ने कहा, "इस मुक़दमे में अभियोजन ने अपनी तरफ से कई गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किये लेकिन अभियोजन अपने मुक़दमे में कोई युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा और इस आधार पर न्यायहित में माननीय न्यायालय ने आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए समस्त आरोपों को खारिज कर मुकदमे में मुलज़ीमानों को बरी कर दिया। वहीं, लम्बी न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे आरोपी विपिन की आँखों में इस अवसर पर ख़ुशी के आंसू छलक रहे थे।"

सीरवी समाज प्रीमियर लीग-7 क्रिकेट प्रतियोगिता व महिला वर्ग खेल क्वार्टरफाइनल संपन्न

परिवहन विशेष न्यूज

हैदराबाद सीरवी समाज प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के सातवें संस्करण व महिला वर्ग में खो खो खेल का क्वार्टरफाइनल चरण संपन्न हुआ। श्री आईमाताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण व आरती के पश्चात प्रतियोगिता के मुख्य प्रयोजक वंडर वाल पट्टी, समाज के गणमान्य अतिथियों एवं टीम के खिलाड़ियों के सान्निध्य में अलियाबाद स्थित सीरवी क्रिकेट ग्राउण्ड में प्रतियोगिता का दुसरा चरण का शुभारंभ किया गया।

आज यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति में फ्रेन्डस क्लब के सुरेश सैणचा ने बताया कि सीरवी समाज प्रीमियर लीग-7 के तहत समाज के विभिन्न क्षेत्रों की 8 टीमों के मध्य टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता के मैच रविवार को खेले गये। महिला वर्ग के खेलों में खो खो खेल की प्रतियोगिता संपन्न हुई तथा क्रिकेट प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला मेडचल व शमशाबाद के मध्य खेला गया, जिसमें मेडचल 24 रन से विजयी रही। एम के चौधरी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ दि मैच से नवाजा गया। दूसरा मैच संगा रेड्डी व

टी एम जी टाइटन्स के बीच खेला गया जीसमे टी एम जी टाइटन्स 22 रन विजयी रहीं ओमप्रकाश चौधरी को मैन ऑफ दि मैच का पुरस्कार दिया गया। तीसरा मुकाबला रामनगर व करमनघाट के माध्य खेला गया, जिसमें रामनगर की टीम 4 विकेट से विजयी रही। राहुल चौधरी को मैन ऑफ दि मैच का पुरस्कार दिया गया। चौथा मुकाबला आईजी फ्रेंड्स कलब व सिकंदराबाद के मध्य खेला गया, जिसमें आईजी फ्रेंड्स कलब की टीम 5 रन से विजयी रही। राजु को मैन ऑफ दि मैच का पुरस्कार दिया गया। पांचवां मुकाबला शमशाबाद व आईजी फ्रेंड्स कलब के मध्य खेला गया, जिसमें शमशाबाद की टीम 84 रनों से विजयी रहीं । प्रेम सिरवी को मैन ऑफ दि मैच का

पुरस्कार दिया गया। छठवां मुकाबला रामनगर व संगा रेड्डी के मध्य खेला गया, जिसमें संगा रेड्डी की टीम ने 18 रन से विजयी रही। मुकेश वोरा को मैन ऑफ दि मैच का पुरस्कार दिया गया। सेमीफाइनल मुकाबले शमशाबाद, टी म जी टाइटन, मेडल व संगा रेड्डी के मध्य खेला जाएगा। महिला वर्ग खो खो के खेल आयोजित हुआ। चिंतल व एल बी नगर बिच फाइनल मुकाबला खेला गया जिसमें एल बी नगर की टीम विजेता रही। उनको सीरवी समाज प्रिमियर लीग 7 के समापन समारोह में पुरस्कृत किया जायेगा।

अवसर पर प्रतियोगिता के स्पॉनसर वंडर वाल पट्टी व समाज के गणमान्य बन्धु उपस्थित रहे। सभी मैचों का सीधा प्रसारण यू- ट्यूब पर और SSPL Application पर किया जा रहा है। सफल आयोजन में सीरवी समाज फ्रेन्डस क्लब के सदस्य उपस्थित रहें।

टीएम कृष्णा को न दें एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश; जानिए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम उपाय के तौर पर कर्नाटक गायक टीएम कृष्णा को एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में मान्यता न दी जाए। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति एसवी एन भट्टी की पीठ ने सुब्बुलक्ष्मी के पोते वी श्रीनिवासन की याचिका पर यह आदेश दिया। श्रीनिवास का आरोप था कि कृष्णा ने दिवंगत गायिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम उपाय के तौर पर कर्नाटक गायक टीएम कृष्णा को एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में मान्यता न दी जाए। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति एसवी एन भट्टी की पीठ ने सुब्बुलक्ष्मी के पोते वी श्रीनिवासन की याचिका पर यह आदेश दिया। श्रीनिवास का आरोप था कि कृष्णा ने दिवंगत गायिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात : सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि ऐसा संज्ञान में है कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी को सभी क्षेत्रों के संगीत प्रेमियों से बहुत सम्मान मिलता है। वह सबसे प्रतिष्ठित गायिकाओं में से एक हैं। श्रीनिवासन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें शहर स्थित संगीत अकादमी द्वारा कृष्णा को पुरस्कार प्रदान करने पर रोक लगाने संबंधी अंतरिम आदेश को खारिज कर दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने मांगा है जवाब : पीठ ने कृष्णा, संगीत अकादमी औरएक प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। यह आदेश तब पारित किया गया जब अतिरिक्त महाधिवक्ता एन. वेंकटरमन ने कहा कि यह एक असाधारण मामला है क्योंकि कृष्णा ने सुब्बुलक्ष्मी को बदनाम करने वाले लेख लिखे थे।

मल्लापुर स्थित सीरवी समाज बडेर मल्लापुर में हाम्बड़ परिवार द्वारा जन्मदिवस पर व हल्दी कार्यक्रम आयोजित अतिथियों के सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित आयोजक दुर्गा प्रसाद हाम्बड़, कमला हाम्बड़ सीरवी समाज अध्यक्ष कालुराम काग, भंगाराम मुलेवा, तुलसाराम सिन्दडॉ, मांगीलाल काग, बाबूलाल मुलेवा, गौशाला अध्यक्ष मंगलाराम पंवार, ओकाराम, सुरेश सैणचा, वेनाराम काग, कानाराम ,राजुराम,नेमीचन्द्र हाम्बड़, तरुण हाम्बड़, महिला मंडल अध्यक्ष पार्वती देवी पंवार, लीला पंवार, कविता चोयल, ललिता भायल, संतोषी सैणचा, पुष्पा सिन्दड़ा, कन्या सिन्दड़ा, अंजु बर्फा,सीतल सैणचा, कविता काग, किरण ,निरमा, संतोषी काग समाज बन्धु उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023